बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 139

## भविष्य के संकेत

सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने रविवार को घोषणा की कि कंपनी वैश्विक स्तर पर अपने मझोले और वरिष्ठ कर्मचारियों की संख्या में दो फीसदी की छंटनी करने जा रही है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कंपनियां खासकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां कारोबारी माहौल में बदलाव को लेकर किस प्रकार प्रतिक्रिया दे रही हैं। टीसीएस की इस घोषणा का अर्थ है कि वह अपने कुल 6 लाख कर्मचारियों में से करीब 12,000 की छंटनी करेगी। कंपनी ने अपने वक्तव्य में कहा कि वह स्वयं को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। इसमें नई तकनीक के क्षेत्रों में निवेश और बड़े पैमाने पर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है। इनका इस्तेमाल कंपनी अपने उपभोक्ताओं के लिए भी करेगी और अपने स्तर पर भी। हालांकि यह आंशिक तौर पर चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल की बदौलत भी हो सकता है लेकिन विश्लेषक इस कदम की व्याख्या एआई के कारण हो रहे ढांचागत बदलाव के रूप में कर रहे हैं।

यकीनन कई बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां मसलन माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और इंटेल ने भी अपने-अपने कर्मचारियों की तादाद कम करने की योजनाओं की घोषणा की है। इस रुझान को समझने में चूक नहीं की जा सकती है। प्रौद्योगिकी जगत तेजी से बदल रहा है और एआई को अपनाने तथा उसकी वृद्धि के साथ न केवल प्रौद्योगिकी कंपनियां बल्कि तमाम क्षेत्रों के कारोबार इसे अपना रहे हैं। इस संदर्भ में टीसीएस प्रबंधन की सराहना की जानी चाहिए कि वह भविष्य की तैयारी कर रहा है और तेजी से बदलते माहौल में प्रासंगिक बने रहने के लिए कड़े निर्णय लेने को तैयार है। केवल वही संगठन मूल्यवर्धन करने, रोजगार तैयार करने और दीर्घावधि में वृद्धि में योगदान कर पाएंगे जो तेजी से बदलते तकनीकी और कारोबारी माहौल को अपनाने के लिए तैयार हों। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि तकनीकी चुनौतियों के अलावा वैश्विक कारोबारी माहौल भी अनुकूल नहीं है। अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीतियों से उपजी अनिश्चितता दुनिया भर में निवेश को प्रभावित कर रही है।

बहरहाल, एआई को अपनाने से कारोबार में बहुत परिवर्तन आ रहा है और भारत जैसे देश के लिए नीतिगत चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि भारत को बड़े पैमाने पर रोजगार तैयार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए एक बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने हाल ही में इस समाचार पत्र से कहा कि वे ऐसे बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां एक ही मॉडल कई ऐसे काम में सहायता करेगा जिन्हें केवल इंसान कर सकते हों। एक बार जब कारोबार ऐसे मॉडल को अपना लेंगे तो वे बहुत बड़े पैमाने पर इंसानों की जगह लेने लगेंगे। परिणामों के मामले में एआई या स्वचालन को अपनाना संतुलन को श्रम के बजाय पूंजी के पक्ष में और अधिक झुका देगा। हालांकि कई क्षेत्रों में यह पहले ही हो रहा है लेकिन मध्यम अवधि में इसमें बहुत अधिक इजाफा होने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत जैसे देश में नीतिगत स्तर पर इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए? दुर्भाग्यवश इनके कोई आसान उत्तर नहीं हैं। नीतियां कंपनियों को तकनीक को अपनाने से नहीं रोक सकती हैं क्योंकि उनके प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए ये आवश्यक हैं। बहरहाल, इससे इंसानी श्रम की मांग जरूर कम होगी।

यकीनन इनके प्रबंधन और संचालन के लिए जरूर प्रतिभाओं की जरूरत होगी। भारत को इन क्षेत्रों में अपनी विशाल तकनीकी श्रम शक्ति को नए सिरे से निर्देशित करके शायद फायदा हो सकता है। शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रशिक्षण को भी अनुकूलित करने की जरूरत हो सकती है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से विभिन्न प्रकार के कार्य भारत आ सकते हैं। बेशक ये सब केवल संभावनाएं हैं और कुछ भी तय ढंग से नहीं कहा जा सकता है। इस समय यकीनन एक व्यापक नीतिगत बहस की आवश्यकता है कि भारत व्यापारिक गुटबाजी और प्रौद्योगिकी द्वारा तेजी से श्रम का स्थान लेने की बढ़ती संभावनाओं के माहौल में जनांकिकी का लाभ कैसे उठा सकता है।

बिनय सिन्हा

# जीएसटी में सुधार के विकल्प और समाधान

**जीएसटी में सुधार की कवायद में ऐसे उपाय अपनाने होंगे जिनसे केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व का ज्यादा नुकसान भी न हो और जो आम जनता को भी पसंद आएं। बता रही हैं आर कविता राव**

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधारों के अगले चरण को लेकर काफी उम्मीदें की जा रही हैं। ऐसी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने जीएसटी में बदलाव की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी परिषद में इस पर चर्चा होने के साथ ही निर्णय लिए जाएंगे। यह वास्तव में राजस्व से जुड़ी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संभावित सुधारों के विकल्पों और उनके प्रभावों का पता लगाने के लिए एक वैचारिक प्रयोग है।

सरकारें और करदाता एवं उपभोक्ता दोनों ही जीएसटी में इन सुधारों से प्रभावित होंगे। सरकारों के लिए, प्रभावी कर दर बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। 11 फरवरी, 2025 को लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि वर्ष 2023-24 के लिए औसत जीएसटी दर 11.64 फीसदी थी जबकि जीएसटी से पहले के दौर में यह 15.8 फीसदी थी। कम से कम, मौजूदा औसत दर और राजस्व के प्रदर्शन को बरकरार रखने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ अपेक्षित तौर पर करदाताओं और उपभोक्ताओं की चिंताओं को देखते हुए कर दरों में कमी की वकालत पर जोर दिया जा सकता है।

इन चिंताओं के समाधान के लिए जीएसटी परिषद के पास दो उपाय हैं: कर की दरों की संख्या यानी कर स्लैब में कमी और क्षतिपूर्ति उपकर में बदलाव करना। जीएसटी लागू होने के बाद से ही कर स्लैब की संख्या कम करना हमेशा से ही जीएसटी सुधारों की चर्चा का एक हिस्सा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के तहत राजस्व की स्थिति स्थिर होने के बाद 12 और 18 फीसदी की 'मानक दरों' को एक ही दर में मिलाकर, दरों की संख्या कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। यह तर्क दिया जाता है कि कई कर दरें, वास्तव में अनुपालन लागत और प्रशासनिक लागत बढ़ाती हैं क्योंकि वे गलत वर्गीकरण के साथ-साथ उलटे शुल्क ढांचे की गुंजाइश बनाती हैं।

कर दरों की संख्या कम करने के संभावित विकल्पों की खोज करते समय विचार करने योग्य दो महत्त्वपूर्ण पहलू हैं: कर दरों के कारण बनी कर राजस्व की संरचना और मांग में उतार-चढ़ाव की संभावित समझ, यानी कर दरों में बदलाव के प्रति मांग की संवेदनशीलता। कीमतों में लचीलेपन से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं होती, लेकिन कर राजस्व की संरचना पर कुछ जानकारी उपलब्ध है।

संसद में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वर्ष 2023-24 में जीएसटी राजस्व संग्रह का लगभग 70-75 फीसदी हिस्सा 18 फीसदी वाले कर स्लैब से आया, जबकि केवल 5-6 फीसदी हिस्सा 12 फीसदी के कर स्लैब से आया। इसके अलावा, 5 फीसदी स्लैब से सिर्फ 6-8 फीसदी राजस्व आया और 28 फीसदी के उच्चतम कर स्लैब ने पिछले वित्त वर्ष में राजस्व में 13-15 फीसदी का योगदान दिया था।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 5 फीसदी और 12 फीसदी दोनों स्लैब, उच्च कर स्लैब की तुलना में कुल राजस्व में बहुत कम योगदान करते हैं। कर दरों में संशोधन करते समय, यदि इन स्लैब पर ध्यान रहा तो राजस्व जोखिम कम से कम हो सकता है। यदि लक्ष्य, कर स्लैब की संख्या कम करना है तब 18 और 28 फीसदी स्लैब में बदलाव करना मददगार नहीं होगा।

ऐसे में कुछ इन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है:

**(क)** 5 फीसदी और 12 फीसदी स्लैब का विलय कर एक 8 फीसदी स्लैब बनाया जा सकता है। चूंकि इन स्लैब का राजस्व में योगदान समान है ऐसे में राजस्व पर प्रभाव न्यूनतम हो सकता है।

**(ख)** अगर 12 फीसदी स्लैब को खत्म कर दिया जाता है तब कुछ वस्तुओं को कम दर पर लाया जा सकता है जबकि अन्य को उच्च दर पर ले जाया जा सकता है ताकि राजस्व तटस्थता बनाई रखी जाए।

**(ग)** 12 फीसदी स्लैब को समाप्त किया जा सकता है और इसकी सभी वस्तुओं को 5 फीसदी स्लैब के दायरे में ले जाया जा सकता है। इससे सरकारों को राजस्व का नुकसान होगा, जो जीएसटी के 5-6 फीसदी के बराबर होगा।

पहले और दूसरे विकल्पों में कुछ राजनीतिक-आर्थिक विचार सामने आ सकते हैं और उन क्षेत्रों से विरोध भी जताया जा सकता है जिनको कर दरों में वृद्धि होती है। विकल्प ग, सरकारों को लागत बढ़ाता है लेकिन यह बात करदाता-उपभोक्ता समुदाय को स्वीकार्य होगी।

जीएसटी सुधार के लिए दूसरे घटक, उदाहरण के तौर पर क्षतिपूर्ति उपकर में बदलाव करते हुए कुछ पृष्ठभूमि की जानकारी ध्यान में रखी जा सकती है। यह उपकर जीएसटी व्यवस्था के तहत संग्रह किए गए कुल राजस्व में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। जीएसटी व्यवस्था में कोई भी सुधार, जिसमें उपकर को समाप्त करना शामिल है उससे राजस्व में कमी आएगी। इसका अर्थ है, वर्ष 2023-24 में 1.44 लाख करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 में 1.49 लाख करोड़ रुपये, या जीएसटी के तहत शुद्ध राजस्व के 7.6 फीसदी की कमी। पहले पांच वर्षों के लिए, राज्यों के 'राजस्व घाटे' को ध्यान में रखते हुए उपकर से हासिल राजस्व की व्यवस्था की गई थी। बाद के वर्षों में, इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार को राजस्व हानि के लिए मुआवजे की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से जुड़े ऋणों की भरपाई के लिए हुआ। दूसरे शब्दों में, पिछले दो वर्षों में, न तो केंद्र और न ही राज्यों की मौजूदा व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्व मिला है। इस संदर्भ को देखते हुए, यह तर्क दिया जा सकता है कि उपकर से मिला राजस्व या इसके बदलाव से मिलने वाला राजस्व, अतिरिक्त उपलब्ध राजस्व होगा। जीएसटी सुधार के ढांचे में इस धारणा को शामिल करने से विकल्पों का दायरा बढ़ सकता है।

क्षतिपूर्ति उपकर को जीएसटी की शीर्ष दरों में मिलाया जा सकता है। यह क्षतिपूर्ति उपकर, मुख्यतौर पर लक्जरी वस्तुओं व सेवाओं, प्रदूषण फैलाने वाले सामान और हानिकारक वस्तुओं पर लगता है। ऐसे में इन करों को बनाए रखना उचित और न्यायोचित माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों की राजस्व संग्रह में समान हिस्सेदारी होगी। उपकर से मिलने वाला राजस्व, 12 फीसदी के स्लैब से मिलने वाले राजस्व के बराबर है। ऐसे में ऊपर दिया गया विकल्प ग राजस्व के लिहाज से तटस्थ हो सकता है यानी इससे सरकारों के राजस्व को कोई नुकसान नहीं होगा। एक और विकल्प यह है कि उपकर को खत्म कर दिया जाए। इससे केंद्र और राज्य के राजस्व में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने के उपाय के तौर पर यह उपाय अपने आप में आम आदमी को पसंद नहीं आता और निष्पक्षता की चिंताओं को अनदेखा कर देता है। जाहिर है, यह उपाय आकर्षक नहीं है।

*(लेखिका एनआईपीएफपी की निदेशक हैं। लेख में व्यक्तिगत विचार हैं)*

# चीन के दुर्लभ खनिज संसाधनों का यथार्थवाद

**दुर्लभ** खनिज तत्त्वों ने तब से सुर्खियां बटोरी हैं जब से चीन ने अमेरिका के साथ अपने व्यापार युद्ध में इन खनिजों के निर्यात (विशेष रूप से दुर्लभ खनिजों से बने स्थायी मैग्नेट) को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है। चीन में वैश्विक दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति का लगभग 70 फीसदी और दुर्लभ खनिज चुंबकों का लगभग 90 फीसदी उत्पादन होता है और इस क्षेत्र में उसका वर्चस्व तुरंत जल्दी खत्म नहीं होगा। दुर्लभ खनिज तत्त्वों और मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध ने हमारे वाहन उद्योग, खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बुरी तरह प्रभावित किया है। इनका इस्तेमाल चिकित्सा उपकरणों, स्मार्टफोन, पवन टर्बाइन, सेमीकंडक्टर, मिसाइलों और विमानों में भी होता है। ऐसे में अगर चीन और अमेरिका के बीच छह महीने का व्यापार युद्धविराम आगे नहीं बढ़ता है तब हमें और अधिक व्यवधानों के लिए तैयार रहना चाहिए।

भारत अब बड़े पैमाने पर मैग्नेट उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है और दुनिया भर में दुर्लभ खनिज आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में ऐसे संसाधनों की पहचान की गई है। हालांकि, भूगर्भीय भंडार का पता लगाने से लेकर खनन, प्रसंस्करण और धातु उत्पादन तक की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि केवल भूगर्भीय संसाधनों की पहचान करना ही भू-राजनीतिक रूप से बहुत मायने नहीं रखता।

चीन ने दुर्लभ खनिजों के उत्पादन में अपनी मजबूत स्थिति दशकों में बनाई है जो एक औद्योगिक रणनीति, तकनीकी अनुसंधान और विकास के साथ ही अपने भूगर्भीय संसाधनों का उपयोग करने पर आधारित है। 1980 के दशक के आखिर में, चीनी योजनाकारों ने रणनीतिक सामग्रियों को चीन की आधुनिकीकरण की योजनाओं में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में पहचाना। तंग श्याओ फिंग को 1992 की शुरुआत में यह बात कहने का श्रेय दिया जाता है कि 'मध्य पूर्व में तेल है जबकि चीन के पास दुर्लभ खनिज हैं।'

ऑक्सफर्ड एनर्जी स्टडीज ने अक्टूबर 2023 के एक शोध पत्र में बताया कि चीन ने वैश्विक बाजारों पर अपना दबदबा कैसे हासिल किया (चीन का दुर्लभ खनिजों पर प्रभुत्व और नीतिगत प्रतिक्रियाएं), और इसके मुख्य कारकों की पहचान की गई जैसे कि उद्योग में शुरुआती कदम, आपूर्ति श्रृंखला के साथ सरकारी निवेश, निर्यात नियंत्रण, कम श्रम लागत और दशकों तक कम पर्यावरणीय मानक आदि। 1990 के दशक में, चीन ने दुर्लभ खनिजों को 'संरक्षित और रणनीतिक खनिज' घोषित किया। इसके अलावा निर्यात कोटा लागू किए गए और दुर्लभ खनिज तत्व सांद्रण के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

चीन में नीतिगत बदलाव वास्तव में उसकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने में मिली सफलता को दर्शाते हैं जिनमें हजारों टन चट्टानों का खनन और तुड़ाई, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अयस्क को और संसाधित करने तथा दुर्लभ खनिज तत्त्वों को अलग-अलग करने के लिए प्रत्येक निष्कर्षण की प्रक्रिया शामिल है। खदान से धातु तक की लागत का लगभग 80 फीसदी ऊर्जा, श्रम और रासायनिक प्रतिक्रिया वाले चटकों में लगता था, जहां चीन की क्षमताओं और लचीले पर्यावरणीय नियंत्रण ने लागत में किफायत दी।

इसके बाद, चीन ने स्थायी मैग्नेट के लिए अमेरिका और जापान में तैयार हुई तकनीक को अपनाया और विश्व-स्तरीय पैमाने के उद्योग तैयार किए। 2000 के दशक की शुरुआत तक, चीन दुर्लभ खनिज और दुर्लभ खनिज उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया और इसकी लागत इतनी कम थी कि अन्य देशों को उत्पादन में कटौती करनी पड़ी या बंद करके अपनी जरूरतें चीन की कंपनियों के माध्यम से पूरी करनी पड़ीं। चीन ने विदेश से कच्चा माल भी हासिल किया। पड़ोसी देश म्यांमार में, उसने विद्रोही काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ सीधे व्यापार किया ताकि टर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसी दुर्लभ खनिज सामग्री का आयात किया जा सके जो मिसाइलों और स्मार्ट हथियारों जैसे रक्षा प्रयोगों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

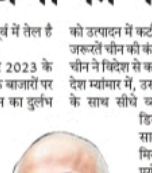
रंजन मथाई

चीन ने वर्ष 2010 में ही यह दिखा दिया था कि वह दुर्लभ खनिज को एक व्यापारिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। उसने एक समुद्री विवाद पर जापान को कुछ महीनों के लिए दुर्लभ खनिज के निर्यात रोक दिया था।

उसी साल निर्यात कोटा (खासतौर पर भारी दुर्लभ खनिज के लिए) में कमी ने अन्य औद्योगिक व्यापारिक साझेदारों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। जापान, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने तब आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने की रणनीतियां अपनाईं, लेकिन इनका सीमित प्रभाव पड़ा, हालांकि जापान की चीन पर निर्भरता में कमी आई। (जापान ने ऑस्ट्रेलिया के खदानों और मलेशिया में एक प्रसंस्करण संयंत्र में निवेश किया। भारत के साथ ऐसे प्रयास हमारी नियामक बाधाओं के कारण विफल रहे।)

चीन से अलग, महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (एमएसपी) की स्थापना जून 2022 में 14 विकसित देशों द्वारा की गई थी। भारत एक साल बाद इस समूह में शामिल हुआ। एमएसपी का अपना कोई फंड नहीं है लेकिन यह निजी पूंजी और सरकार-समर्थित धनराशि को महत्त्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें दुर्लभ खनिज प्राथमिकताओं में शामिल है। चीन ने एमएसपी को 'पूर्ण प्रतिस्पर्धी' के लिए एक पश्चिमी साधन के रूप में देखा, लेकिन यह आश्वस्त रहा कि दुर्लभ खनिज में उसके प्रभुत्व को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास ऊपरी स्तर पर खनन, मध्यवर्ती स्तर पर गलाने और निचले स्तर की इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक के लिए उपकरण थे जिसका उसको लाभ मिला।

दशकों के अनुभव से पता चलता है कि चीन का आत्मविश्वास पूरी तरह गलत नहीं था। वह वैश्विक बाजारों में अपना दबदबा बनाए हुए है क्योंकि खदान से मैग्नेट बनाने तक का सफर तकनीकी रूप से बेहद जटिल और फिलहाल बहुत प्रदूषण फैलाने वाला है। निष्कर्षण, प्रसंस्करण और अलगाव की आर्थिक प्रक्रियाओं में चीन को मिले फायदे ने वहां की कंपनियों को प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए कीमतों में हेरफेर करने में सक्षम किया है। चीन तकनीकी जानकारी पर सख्त नियंत्रण रखता है और विशेषज्ञों की विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा रहा है। साथ ही, वह उन पर्यावरणीय लागतों का 'प्रबंधन' करता है जिनसे कहीं और की परियोजनाओं की मंजूरी में देरी होती है। अमेरिका में, पेंटागन ने अब घरेलू मैग्नेट उत्पादन में तेजी लाने के लिए एक दुर्लभ खनिज उत्पादक कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है।

भारत के पास दुर्लभ खनिज, खासतौर पर हल्की दुर्लभ खनिज की मोनाजाइट और समुद्री रेत से निकालने का लंबा अनुभव है। लेकिन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ज्ञात भंडार होने के बावजूद, भारत का उत्पादन चीन के उत्पादन के 2 फीसदी से भी कम है।

नीतिगत और नियामक बाधाएं भविष्य में संसाधनों की खोज और इससे जुड़े विकास की राह में बाधा बनती हैं। खनन और प्रसंस्करण के प्रति जन विरोध की वजह से भी मदद नहीं मिली है। जब तक औद्योगिक दस्तूर में कोई बदलाव नहीं होता और सरकार तथा नागरिक समाज खनन के महत्त्व को नहीं पहचानते, तब तक महत्त्वपूर्ण खनिज भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बने रहेंगे।

*(लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं)*

## आपका पक्ष

**कर विवाद समाधान करती ट्रांसफर प्राइसिंग**

संपादकीय 'ट्रांसफर प्राइसिंग: बढ़ेगा विवाद' अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के विभिन्न देशों में आयकर निर्धारण संबंधित मामलों पर सार्थक चर्चा करता है। ट्रांसफर प्राइसिंग के नियम सभी देशों में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के समझौतों, नियमों और मानकों पर आधारित हैं और यह उनकी बाध्यता है। वैश्विक व्यापार में भागीदारी करने वाले देशों के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग के नियम उनके आयकर अधिनियमों में सम्मिलित हैं, यह बात अलग है कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के दुरुपयोग करने में पीछे नहीं हैं। वे दूसरे देशों को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात, संयुक्त उपक्रमों और द्विपक्षीय व्यापार में अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने और अपने स्थायी देश में अपना लाभ स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग के कानूनों का आश्रय लेती हैं। हमारे देश में

ट्रांसफर प्राइसिंग के नियम सभी देशों में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के समझौतों, नियमों और मानकों पर आधारित हैं

उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में कर विवाद मामलों के निस्तारण में बहुत लंबा समय लगता है, जिससे हमारी कर प्रणाली की साख पर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग के नियम संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत भी सृजित हैं परंतु वैश्विक स्तर पर उनका अनुपालन नहीं होता और ओईसीडी के नियमों पर ही आधारित ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों का सभी देशों में अनुपालन होता है। इसके अतिरिक्त आपसी दोहरे कर बचाव समझौतों (डीटीएए) के प्रावधानों और एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से भी आयकर निर्धारण संपन्न होते हैं जिनमें विवाद की संभावना नहीं रहती। अतः प्रयास यही होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के कर निर्धारण में विवाद नहीं होने चाहिए जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले और भारत की आयकर प्रणाली की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो।

*विनोद जौहरी, दिल्ली*

**बुनियादी ढांचा ऐसा हो कि हादसे कम हों**

सड़कें, पुल, सुरंग, कार्यालय भवन, विपणन भंडार आदि के निर्माण मजबूत हो तथा निर्माण में लापरवाही नहीं होना चाहिए। दरार या दोष मिलने पर निश्चित समयावधि में ढांचा गिरा दिया जाए। जन-धन हानि और हादसों से बचने के लिए समय अनुसार रखरखाव, जांच और सुधार की सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तथा जिम्मेदारी तय करते हुए लापरवाहों को बख्शा भी नहीं जाए।

*बी एल शर्मा, उज्जैन*

**रखरखाव के लिए नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल हो**

बुनियादी ढांचे से जुड़े हादसे रोकने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण और नियमित रखरखाव तकनीक पर ध्यान देना होगा। साथ ही सुरक्षा मानकों का पालन करना, प्रशिक्षण में जागरूकता तथा नियमित निरीक्षण पर ध्यान देना चाहिए। फिर इसे डिजाइन एवं योजनानुसार भी समझना जरूरी है। हमें बुनियादी ढांचे से जुड़े हादसे रोकने में सामर्थ्य हासिल करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सार्वजनिक तौर पर भी जागरूकता आवश्यक है। हमें जोखिम का मूल्यांकन एवं प्रबंधन करते रहना होगा।

*मनमोहन राजावत, शाजापुर*

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : letters@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

## देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह स्थित फायर ऐंड फ्यूरी कोर के मुख्यालय और सियाचिन ब्रिगेड का दौरा किया, जहां उन्होंने सैन्य अभियानों की परिचालन तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने विश्व की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सभी रैंकों के कर्मियों की उनकी पेशे और अनुकरणीय सेवा के लिए सराहना की।

अमर उजाला
# प्रवाह
7 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा
नई दिल्ली ■ मंगलवार, 29 जुलाई 2025

अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हम कैसे सशक्त बना सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। -मैगी हासन

**देश की बड़ी आबादी जब कुछ अतिरिक्त आय के लिए अपनी जमा-पूंजी पूरे भरोसे के साथ बैंक में रखती हो, तब केंद्रीय बैंक की नवीनतम बुलेटिन के अनुसार कुछ सार्वजनिक और निजी बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दरों का ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंचना बेहद चिंताजनक है।**

# बचत का ब्याज

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की हालिया बुलेटिन के अनुसार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दरों का ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंचना चिंताजनक तो खैर है ही, यह स्थिति वैश्विक क्षेत्र के साथ, आम नागरिकों और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर विचार का विषय है। उल्लेखनीय है कि 2011 में जब केंद्रीय बैंक ने बचत खाते की ब्याज दरों को नियमनमुक्त कर बैंकों को स्वतंत्र रूप से दरें निर्धारित करने की अनुमति दी थी, तो उसका उद्देश्य बाजार आधारित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। लेकिन, आज सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों के बचत खातों पर ब्याज दरों का 2.5 फीसदी के निम्न स्तर पर पहुंचना इसलिए भी अधिक चिंताजनक है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी, खासकर बुजुर्ग, पेंशनभोगी, गृहणियां और वेतनभोगी वर्ग, अब भी अपनी छोटी-छोटी बचत बैंकों में रखती है, ताकि उस पर कुछ अतिरिक्त आय मिल सके। लेकिन ब्याज दर में गिरावट के दौर में ब्याज से होने वाली आय महज औपचारिकता ही बनती जा रही है। दरअसल, केंद्रीय बैंक के अनुसार, फरवरी, 2025 से नीतिगत रेपो दर में सौ आधार अंकों की कटौती के जवाब में बैंकों ने अपनी ऊधार दरों को समायोजित किया है और इसी वजह से वाणिज्यिक बैंकों के नए और बकाया ऋणों पर भारित औसत उधार दरें कम भी हुई हैं। अब यह स्थिति सवाल उठाती है कि कम ब्याज दरें अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रोत्साहन दे रही हैं? छोटे जमाकर्ता, जो अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर निर्भर हैं, अब कम रिटर्न के चलते निवेश के अन्य जोखिम भरे विकल्पों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इससे बैंकों के लिए जमा आधार को बनाए रखने में भी मुश्किल आ सकती है। यही नहीं, सरकार ने सितंबर तिमाही के दौरान छोटी बचत योजनाओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे छोटे निवेशक छोटी बचत

योजनाओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे बैंकों का जमा आधार और कमजोर हो सकता है। केंद्रीय बैंक और सरकार को इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। एक ओर, जहां नीतिगत दरों में कटौती का उद्देश्य उधार को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना है, वहीं दूसरी ओर, बचत खातों पर ब्याज दरों का अत्यधिक कम होना छोटे जमाकर्ताओं के भरोसे को कमजोर कर सकता है। इस संदर्भ में, बैंकों को अपनी नीतियों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। कम ब्याज दरें अल्पकालिक आर्थिक प्रोत्साहन के लिए फायदेमंद बेशक हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता के लिए बचत और निवेश के बीच संतुलन जरूरी है।

## जीवन धारा

जेम्स एलन

परिस्थिति कैसी भी हो, आप वही करें, जो सत्य की कसौटी पर खरा हो। इस विश्वास की सहायता से आपकी हानि लाभ में बदल जाएगी; सभी विपत्तियां, जो भयभीत कर रही हैं, आशीर्वाद का रूप धारण कर लेंगी।

## जो संतुष्ट है वही धनी है

*जिसके हृदय में ईमानदारी, विश्वास, दया और सच्ची समृद्धि प्राप्त करने की उत्कट इच्छा होती है, वही व्यक्ति समृद्धि का अनुभव कर सकता है। जिसमें यह गुण नहीं, वह समृद्धि को जान नहीं सकता, क्योंकि यह बाहरी संपदा नहीं, बल्कि अंतःकरण की एक अनुभूति है। लालची व्यक्ति लखपति भी हो जाए, तब भी वह दूसरों को अपने से अधिक धनी देखकर सदैव दुखी, दरिद्र और भिखारी बना रहेगा। इसके विपरीत ईमानदार, उदार और सहृदय व्यक्ति अक्षय संपदा प्राप्त करेगा, चाहे उसकी भौतिक संपत्ति बहुत थोड़ी ही क्यों न हो। भिखारी वही है, जो असंतुष्ट है। अपने पास की संपत्ति से संतुष्ट रहने वाला ही धनी है और वह यदि करुणा के वश में अपनी संपत्ति दोनों हाथों से बांटता है, तो वह उस संतोषी से भी अधिक धनी है।*

*जिस समय हम यह देखते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों तरह की संपदा विश्व में भरी पड़ी है और जब हम इसका मुकाबला उस मनुष्य से करते हैं, जो कुछेक सिक्कों या कुछेक एकड़ भूमि की कमाई से प्रसन्न है, तो हमको पता चलता है कि स्वार्थ कितना अंधा और अज्ञानमय है। इसी समय हमको अनुभव होता है कि स्वार्थ की पूर्ति की अभिलाषा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। प्रकृति बिना कोर-कसर के ही सब कुछ उठाकर दे देती है, पर तब भी उसकी कृपा हानि नहीं होती। मनुष्य सब कुछ को हड़पने में ही अपना सब कुछ खो बैठता है। अगर आप सच्ची समृद्धि पाना चाहते हैं, तो आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ठीक-ठीक काम करने पर हर चीज आपके प्रतिकूल हो जाएगी और आप विफल होकर रह जाएंगे।*

*सत्य में जो आपकी निष्ठा है, उसे दूसरों के साथ प्रतियोगिता में हाथ से जाने न दीजिए। इस संबंध में मैं लोगों की राय की अधिक परवाह नहीं करता। मैं प्रकृति के अटल नियम को बखूबी जानता हूं। इसलिए मैं बेहिचकी के हरेक चरण को उंठे दिल से देख सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका अंतिम परिणाम है- विनाश। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, आप वही कीजिए, जो सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हो। इस विश्वास की सहायता से आपकी प्रत्येक हानि लाभ में बदल जाएगी; सभी विपत्तियां, जो इस समय भयभीत कर रही हैं, आशीर्वाद का रूप धारण कर लेंगी। ईमानदारी, उदारता और प्रेम को कभी दूर न होने दीजिए, क्योंकि शक्ति का संयोग होने पर ये ही आपको असल समृद्धिशाली दशा में पहुंचा सकते हैं। जब दुनिया आपसे कहे पहले अपने-आप पर ध्यान दीजिए, बाद में दूसरों पर, उस समय आप उनकी बातों में न आइए। जो लोग ऐसा करने के आदी हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि उनको सभी त्याग देंगे और फिर जब दुख तथा एकांत में वे रोएंगे, आंसू पोंछने वाला उनको कोई न मिलेगा। दूसरों से पहले अपना ही ध्यान रखना, ईश्वर की दी हुई विभूति को व्यर्थ होने जाना है। अपना हृदय उदार कीजिए। इसका फल यह होगा कि आपकी प्रसन्नता स्थायी होगी और सभी ऋद्धि-सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी।*

## श्रेष्ठता के गुणों का संचय करें

*जो लोग सच्चाई के मार्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, वे कदम-कदम पर प्रतियोगिता में आकर गलत हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन जो लोग सदा उचित रास्तों पर चलते हैं, उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाले सभी गुणों का संचय कीजिए। इससे आप सभी बुराइयों से बच जाएंगे।*

सूत्र

# ट्रंप के समझौतों का मकसद एक ही है

**टैरिफ की धमकी देकर देशों को अमेरिका-जापान सरीखे आर्थिक समझौतों के लिए मजबूर करना वैश्वीकरण के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए, भारत को अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करते हुए उन्हीं मानकों का ध्यान रखने की जरूरत है, जिन्हें ब्रिटेन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते में अपनाया गया।**

पिनाकी चक्रवर्ती
एनआईपीएफपी के पूर्व निदेशक

बीती 23 जुलाई को अमेरिका-जापान के बीच हुआ व्यापार समझौता बेहद असंतुलित है और यह अमेरिका को असंगत लाभ प्रदान करता है। इस व्यापार समझौते का प्रावधान अमेरिका को 25 फीसदी के बजाय 15 फीसदी का पारस्परिक शुल्क लगाने की अनुमति देता है। कम पारस्परिक शुल्क का मतलब केवल यही है कि अमेरिका को वह मिल गया, जो वह चाहता था। किसी व्यापार समझौते के आधार पर पारस्परिक टैरिफ किस दर से लगाया जाएगा, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है।

इसके बावजूद, जहां तक अमेरिका का सवाल है, तथ्य यह है कि पहले प्रस्तावित टैरिफ की तुलना में कम टैरिफ लगाने से अमेरिका को जापानी निर्यात की लागत कम होने की उम्मीद है। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में स्थिरता का भाव भी लाता है और सेमीकंडक्टर, फार्मास्युटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में अमेरिका में 500 अरब डॉलर के जापानी निवेश की भी अनुमति देता है। संक्षेप में, यह समझौता अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अधिक व्यापार संरक्षण और जापानी एफडीआई के जरिये अमेरिका में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद से ही अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वर्गर किसी ताम्झाम के उनकी चिंता जायज है। चीन से आने वाले सस्ते आयात के कारण अमेरिका में विनिर्माण क्षेत्र लगभग न के बराबर बचा है। अमेरिका में जापानी निवेश की अनुमति विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए है। इस दृष्टि से, यह व्यापार समझौता अमेरिका में विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में उठाया गया कदम भी है। अब सवाल उठता है कि इस व्यापार समझौते से बदले में जापान को क्या मिलेगा। इसका जवाब है-कुछ खास नहीं।

मोटे तौर पर कहें, तो अमेरिकी बाजार में जापानी कारों के लिए शायद

एक स्थिर बाजार पहुंच मिले। यह अमेरिका के लिए भले ही बड़ी बात हो, लेकिन जापान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि जापान इस समझौते के लिए क्यों राजी हुआ। इसका मुख्य कारण संभवतः जापानी जीडीपी में ऑटोमोबाइल का सापेक्षिक महत्व हो सकता है। जापानी जीडीपी में ऑटोमोबाइल क्षेत्र का हिस्सा 2.9 फीसदी है और यह जापान के विनिर्माण जीडीपी का लगभग 14 फीसदी है।

ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक कम्प्लेक्सिटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2023 में, वैश्विक कार निर्यात में जापान की हिस्सेदारी 12.2 फीसदी थी और 36 फीसदी जापानी कारें अमेरिका को निर्यात की गईं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि चूंकि कनाडा और मैक्सिको के लिए पारस्परिक टैरिफ 25 फीसदी लगाए जाने की उम्मीद है, इसलिए अमेरिका के बाजार में पहुंच के मामले में जापान को इन देशों की तुलना में बढ़त मिलती है। इससे जापानी कार निर्माताओं को मदद मिल सकती है।

अगर हम कृषि की बात करें, तो यह समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को जापानी बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करता है। वर्ष 2022 में, अमेरिका के कुल वैश्विक कृषि निर्यात का लगभग 7.7 फीसदी जापान को भेजा गया था। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, यह 14.9 अरब डॉलर मूल्य के कृषि उत्पादों के बराबर था। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अनुसार, जापान अमेरिकी कृषि निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, और लगातार इन उत्पादों के लिए शीर्ष गंतव्यों में शुमार है। भले ही यह समझौता अमेरिका और जापान के बीच हुआ हो, लेकिन भारत के लिए भी इसके कुछ महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, खासकर तब, जब भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। फिलहाल, अमेरिका ने जापान के लिए 15 फीसदी पारस्परिक शुल्क लगाया है, जो भारत सहित अमेरिका द्वारा घोषित अधिकांश अन्य पारस्परिक शुल्कों से कम है। इस तरह से देखें, तो अमेरिकी बाजार में पहुंच के मामले में भारत जापान के मुकाबले नुकसान में है।

ऐसे में, अमेरिका-जापान व्यापार समझौते का हवाला देते हुए भारत अमेरिकी कृषि बाजार में पहुंच के लिए बड़ी रियायत की मांग कर सकता है। जापान के विपरीत, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी हुई है। कृषि क्षेत्र को खोलना मुश्किल हो सकता है और शायद अभी ऐसा करने का समय नहीं आया है। चूंकि, भारत पहले ही ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है, इसलिए उस समझौते के विभिन्न प्रावधान भी एक मानक के रूप में काम करेंगे। किसी भी कठिन वार्ता को इस बात पर आधारित होना होगा कि क्या संभव है और क्या व्यवहार्य है, यह ब्रिटेन-भारत व्यापार समझौते के तहत भारत द्वारा हासिल की सहमत बातों से अलग होगा।

अमेरिका-भारत व्यापार समझौते का नतीजा चाहे जो भी हो, बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका टैरिफ की धमकी को हथियार बनाकर आक्रामक रुख अपना रहा है, ताकि विभिन्न देशों को अमेरिका के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते करने के लिए मजबूर किया जा सके। यह व्यापक वैश्वीकरण के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि उसने जापान के बाद यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भी पारस्परिक टैरिफ समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। अमेरिका और ईयू के बीच हुए समझौते के तहत ईयू पर 15 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा, इस समझौते के तहत ईयू अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

ये रणनीतिक स्तर विभिन्न देशों से संबंधित सौदे हर देश को उतना फायदा नहीं पहुंचाएंगे, जितना वैश्वीकरण से उम्मीद की जा रही थी। इस तरह के सौदे वैश्विक बाजार को खंडित कर देंगे और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में तनाव ही बढ़ाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा बढ़ता संरक्षणवाद वैश्विक व्यापार व्यवस्था के खेल में छोटे खिलाड़ियों द्वारा अपनाए गए संरक्षणवाद से अलग है। अब समय आ गया है कि बाजार के विश्वंडन से आगे सोचा जाए और यह अमेरिका के साथ देशों से संबंधित विशिष्ट व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके नहीं किया जा सकता। हम इसे जितनी जल्दी समझ लें, उतना ही बेहतर है।

edit@amarujala.com

## दूसरा पहलू

नीदरलैंड की राजधानी में साठ फीसदी से ज्यादा आबादी आवागमन के लिए प्रतिदिन साइकिल का इस्तेमाल करती है।

# एम्स्टर्डम की अनूठी साइकिल संस्कृति

**नीदरलैंड** की राजधानी एम्स्टर्डम अपनी अनूठी 'साइकिल संस्कृति' के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर की 60 फीसदी से अधिक आबादी आवागमन के लिए प्रतिदिन साइकिल का इस्तेमाल करती है। साइकिल यहां 'स्टेटस सिंबल' तक बन चुकी है। एम्स्टर्डम ऐसा शहर है, जहां की सड़कों और गलियों को साइकिल चालकों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। दशकों की मेहनत के बाद एम्स्टर्डम ने अपनी विशिष्ट साइकिल संस्कृति विकसित की।

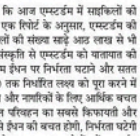

सुधीर कुमार

1890 के दशक में पहली बार एम्स्टर्डम की सड़कों पर साइकिल दिखाई दी, तब इसे सिर्फ मनोरंजन का साधन माना गया था। हालांकि, 1973 के तेल संकट ने इस परिदृश्य को एक बार फिर बदल दिया। अरब निर्यातक देशों द्वारा नीदरलैंड समेत कई देशों पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप तेल की कीमत चौगुनी हो गई। इसी बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री जूप डैन उइल द्वारा उच्च नगरिकों से जीवनशैली में बदलाव लाने और ऊर्जा बचत के आह्वान ने लोगों को टिकाऊ परिवहन की ओर आसरा दिया।



साइकिल के प्रति बढ़ते क्रेज का नतीजा है कि आज एम्स्टर्डम में साइकिलों की संख्या वहां की करीब आठ लाख आबादी से पचास हजार ज्यादा हो गई है।

साइकिल के प्रति बढ़ते क्रेज का नतीजा है कि आज एम्स्टर्डम में साइकिलों की संख्या वहां की आबादी लगभग आठ लाख है, जबकि साइकिलों की संख्या साढ़े आठ लाख से भी अधिक पहुंच चुकी है। इस अनूठी साइकिल संस्कृति से एम्स्टर्डम को यातायात की भीड़ व वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और सतत विकास को बढ़ावा देकर 'नेट जीरो' के 2050 तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिली है। यह 'जीवन प्रत्याशा' को सुधारने और नागरिकों के लिए आर्थिक बचत का माध्यम भी बन रहा है। बहरहाल, साइकिल परिवहन का सबसे किफायती और पर्यावरणहितैषी साधन है। इसे प्राथमिकता देने से ईंधन की बचत होगी, निर्भरता घटेगी और प्रदूषण-मुक्त समाज का स्वप्न भी साकार हो पाएगा। इस मामले में हमें एम्स्टर्डम से सीखने की जरूरत है।

## आंकड़े

### यूपीआई लेनदेन

हाल ही में आईएमएफ की रिपोर्ट में भारत को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में सबसे आगे बताया है, जिसमें यूपीआई का योगदान सबसे ज्यादा है।

| | |
|---|---|
| महाराष्ट्र | 8.80% |
| कर्नाटक | 5.61% |
| उत्तर प्रदेश | 5.5% |
| तेलंगाना | 4.94% |
| तमिलनाडु | 4.37% |

आंकड़े यूपीआई ट्रांजेक्शन वाले शीर्ष राज्यों के, प्रतिशत में | स्रोत : NCPI, SBI Research

संत ने सेठ से कहा कि भगवान ने तुम्हें प्रायश्चित का मौका दिया है। इसलिए अपने पुराने सेठ से चोरी के लिए माफी मांगो और अपने कर्म क्षमा करवाओ।

# राम नाम के जप का असर

एक सेठ का कारोबार अच्छा चल रहा था। ईश्वर प्रेरणा से उन्हें लगा कि धन तो बहुत कमा लिया, अब परलोक के लिए भी कमाई कर ली जाए, तो उन्होंने एक संत से राम नाम की दीक्षा ली। सेठ जी ने राम नाम का जप शुरू किया, तो उनके दबे हुए पूर्व कर्म जागृत हो उठे। अब जैसे-जैसे उनका जप और ध्यान बढ़ता जा रहा था, वैसे-वैसे उनकी बेचैनी भी बढ़ने लगी। एक दिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्मशान से लौटे, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया।

उन्हें रोते-रोते तीन दिन बीत गए। घर वाले उन्हें संत के पास लेकर पहुंचे। गुरु ने रोने का कारण पूछा, तो सेठ जी बोले, 'महाराज मैं पहले अमुक सेठ के यहां काम करता था। उनका मेरे ऊपर बहुत विश्वास था। एक दिन मैंने उनके दो लाख रुपये चुरा लिए व नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर लिया। मेरा काम चल निकला। मुझे यह भय सता रहा है कि मैं उस पाप का बोझ लेकर मरूंगा।' गुरु महाराज ने कहा, यह तो राम नाम के जप और ध्यान का असर है, जो तुम्हें अपने पाप कर्म का एहसास हो रहा है। ईश्वर ने तुम्हें प्रायश्चित का मौका दिया है। इसलिए तुम उन्हीं सेठ के पास जाओ और ब्याज सहित पूरा पैसा चुकाकर उनसे माफी मांग कर अपने कर्म क्षमा करवाओ। सेठ ने ऐसा ही किया, वह अपने पुराने सेठ के पास रुपये लेकर पहुंचा और पूरी बात बताकर क्षमा-याचना की। उन सेठ ने कहा, 'मुझे तो पता भी नहीं था कि तुमने मेरे यहां चोरी की थी, यह तो मेरी लॉटरी लग गई।'

अंतर्यात्रा
संकलित

## अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 29 जुलाई, 1953

### उत्तर कोरिया ने कहा-अमेरिका की कमर तोड़ी, पर सतर्क रहें

पुनर्निर्माण के कार्यों में जुटजाओ

**उत्तर कोरिया के युवा राष्ट्रपति मार्शल किम्फ्रस्संग ने कहा, 'साथियो, इस युद्ध में साम्राज्यवादी अमेरिका की कमर तोड़ दी गई है। अब यह लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, फिर भी हमें उससे सतर्क रहना है।'**

# शहर स्वच्छ कैसे रखे जाते हैं

**स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के नतीजे बताते हैं कि नगरीय निकायों के अलावा शहरवासियों का योगदान अपने शहर को स्वच्छ रखने में ज्यादा रहता है।**

ऋतुपर्ण दवे

स्वच्छता

चंदौरों का शहर, अपनी संस्कृति और धरोहर को सहेजे रखने वाला इलाका, अदब के साथ पेश आने वालों से भरा मिनी मुंबई कहलाने वाला शहर एक बार फिर देश में अव्वल आया। मालवा के इस शहर के लोग एक-दूसरे को बधाई देते यह कहते नहीं अघाते 'भिया अपणो इंदौर चकाचक तो हुई ग्यो, अपणों इंदौर फिर टॉप आग्यो...।' स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के नतीजों को लेकर यहां के लोगों की निश्चिंतता थी, क्योंकि इसके लिए वे हर दिन जूटे रहते थे।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इस बार कई बरसों से स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल रहने वाले शहरों के लिए सुपर स्वच्छता लीग की शुरुआत की, ताकि जो शहर हर बार टॉप कर रहे हैं, वे आदतन बदल चुके हैं और इनका मुकाबला स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरे शहरों से होगा, तो और सुधार होगा। लेकिन सुपर स्वच्छता लीग में भी इंदौर ने ही टॉप किया। इंदौर की यह उपलब्धि महज प्रासंगिक प्रयास नहीं है, बल्कि वहां के प्रत्येक नागरिक की भी

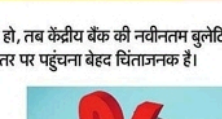

सामूहिक जिम्मेदारी की दौड़ है। दरअसल, मालवा के इस शहर की फितरत ही ऐसी है कि जो ठाना उसे पाना।

इंदौर ने तीन-आर पर काम किया: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, लेकिन अब एक और बड़ी रिजोल्यूस पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इंदौर में कचरे से नई उपयोगी चीजें बनेंगी। जैविक कचरे से खाद, प्लास्टिक और अन्य अनुपयोगी वस्तुओं को रिसाइकल कर नए उत्पाद बन रहे हैं। इंदौर में कचरा अब कचरा नहीं, कमाई का जरिया भी बन गया है।

इंदौर ने अभी से आगे भी अपनी बादशाहत बरकरार रखने की तैयारी भी शुरू कर दी है। नगर निगम ने जीरो लैंड फ्री सिटी की ओर भी कदम बढ़ा दिए हैं। इसके जरिये न केवल प्रोसेसिंग के बाद बचने वाले करीब पांच प्रतिशत अनुपयोगी सूखे कचरे को जमीन के नीचे दबाकर एक लेयर तैयार की जाएगी, इससे जमीन में लैंड फिलिंग का काम होगा। नगर निगम की कोशिश वेस्ट मैटेरियल से बिजली बनाने की भी है। अभी इंदौर में ट्रीटेड सीवर वाटर के जरिये भवन निर्माण के क्षेत्र में इसका उपयोग कर अच्छी शुरुआत की गई है, जिसके बेहतर नतीजों के साथ कमाई भी हो रही है। इस तरह इंदौर में घरों के बाथरूम और किचन के खराब पानी का सदुपयोग भी बड़ा कामयाब रहा।

इंदौर का स्वच्छता में पंचम फहराने के पीछे आज की मेहनत तो है, पर असल शुरुआत 1913 में होलकर राज्य में तभी हो गई थी, जब शहर में गंदगी करने वालों पर जुर्माना लगने लगा था। 1970-80 के दशक में जब इंदौर नया आकार ले रहा था और कॉलोनियों की शुरुआत हुई, तब भी सफाई को खूब तवज्जो दी गई। बेशक इंदौर की कॉलोनियों का चकाचक होना 2014 के बाद सफाई को लेकर शुरू हुए राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बन गया है, जब पहली बार देश में इसको लेकर स्वच्छ शहर अवॉर्ड की शुरुआत हुई।

भारत में पहली बार घर-घर डस्टबीनों में कचरा संग्रह कराने की मुहिम इंदौर से ही शुरू हुई, जो मील का पत्थर भी साबित हुई। बाद में गीले-सूखे कचरे संग्रह की शुरुआत हुई। गीले कचरे के शोधन के लिए आसपास संयंत्र लगाए गए। दिल्ली समेत दूसरे कई महानगरों सरीखे इंदौर में भी देवगुराड़िया गांव के पास कचरे के ढेर मुंह चिढ़ाते थे। वहां पहाड़ लाख टन कचरे को खत्म करने की शुरुआती पहल से सभी का ध्यान इंदौर की ओर गया और पहली बार 2017 में इंदौर ने देश के स्वच्छ शहर का खिताब न केवल अपने नाम किया, बल्कि आज तक बरकरार भी रखा।

इंदौर नगर निगम का वार्षिक बजट आठ हजार करोड़ रुपयों से ज्यादा है। इसमें दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा स्वच्छता के लिए बताए जा रहे हैं। इसमें में वेतन एवं अन्य विविध व्यय भी शामिल हैं। यहां के लोगों से उपयोगकर्ता यानी यूजर चार्ज शुल्क भी बहुत मामूली वसूला जाता है। झुग्गी-झोपड़ियों से 60 रुपये, मध्यम वर्ग से 90 रुपये और सोप्पों से 150 रुपये हर घर का मासिक शुल्क लिया जाता है। निश्चित रूप से यह न केवल जनभागीदारी है, बल्कि इससे जिम्मेदारी भी बनती है।

शहर के साफ-सफाई में अव्वल आने से लोगों की मानसिकता बदली है। इंदौरियों में स्वच्छता का संस्कार इस कदर समा गया है कि वे खुद भी इधर-उधर कचरा नहीं फेंकते और दूसरों को भी नहीं फेंकने देते। कूड़ा तो दूर, लोगों की सड़कों पर जहां-तहां थूकने की आदत भी बदल गई है। इससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के अलावा दूसरे फायदे भी नजर आ रहे हैं, जहां स्थायी संपत्तियों की दरें बढ़ रही हैं, वहीं निवेशक भी इंदौर की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। चकाई इंदौर दूसरे शहरों के लिए मिसाल बन गया है। कितना अच्छा होता कि सब इंदौर मॉडल को अपनाते। हां, चकाई इंदौर के साथ-साथ उन सभी को बधाई है, जिन्होंने किसी न किसी श्रेणी में स्थान हासिल किया है।

हिन्दुस्तान

# बहस में सिंदूर

संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जब बहस शुरू हो रही थी, तब कश्मीर में भारतीय सेना के नेतृत्व में ऑपरेशन महादेव चल रहा था। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सुलेमान शाह सोमवार को मुठभेड़ के दौरान मारे गए तीन आतंकियों में शामिल था। यह सफल अभियान जैसे समन्वय के साथ पूरा किया गया है, इसकी सराहना होनी चाहिए। इससे रक्षा और सुरक्षा बलों के मनोबल में बढ़ोतरी होगी। अगर सुरक्षा बलों का दावा सही है, तो यह एक बड़ी शुरुआत है। यह मांग अक्सर उठती है कि पहलगाम हमले के दोषी आतंकियों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। जो आतंकी भारत की सीमा में हैं, उन्हें सक्रिय होने का मौका कतई नहीं देना चाहिए। आंतरिक रूप से आतंकवाद के खतरे को समाप्त करना प्राथमिकता होनी चाहिए। जो आतंकी भारतीय संविधान को नहीं मानते, जिनका मकसद भारतीयों को रुलाना है, उनके लिए भारत भूमि पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आतंकियों पर लगाम कसना स्वयं भारतीय सेना के लिए आवश्यक है। विगत महीनों से सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ी है और सबसे खुशी की बात है कि तकनीकी हवाई निगरानी को बढ़ाया गया है।

ऑपरेशन महादेव की सफलता का श्रेय जम्मू-कश्मीर की पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना, तीनों को दिया जा रहा है। तीनों की एकजुटता से ही आतंक विरोधी अभियानों में सफलता मिल रही है और आगे भी मिलेगी। कश्मीर में चप्पे-चप्पे को सुरक्षित बनाने के लिए ऑपरेशन महादेव जैसे कारगर अभियानों की जरूरत है। ऐसे अभियानों के बल पर ही जम्मू-कश्मीर में बचे हुए आतंकियों का खात्मा किया जा सकता है। गौर करने की बात है कि जैसे समन्वय से कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान चल रहा है, ठीक वैसे ही समन्वय की उम्मीद संसद से भी है। ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही बहस से विपक्ष व देश को अनेक सवालों के जवाब मिलेंगे, वहीं सत्ता पक्ष को जरूरी सुधार या चिंतन की प्रेरणा मिलेगी।

**लोकसभा में बहस के बाद मंगलवार को राज्यसभा में बहस होगी और जो निचोड़ सामने आएगा, उसका देश के लिए संदेश सकारात्मक होना चाहिए।**

वास्तव में, देश की सुरक्षा-रक्षा से जुड़े मामलों में संसद में समन्वय बहुत जरूरी है। संसद में इस मामले पर बहस केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि किसी दल को अपने मतदाताओं को संतुष्ट करना है या किसी दल को नीचा दिखाना है। बहस इसलिए होनी चाहिए कि दलों के बीच परस्पर विश्वास बढ़े। सकारात्मक बहस हो, जिससे ठोस नतीजों तक पहुंचने में मदद मिले। सांसदों को फिजूल हंगामों से बचना चाहिए और देश-दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि भारत में राजनीतिक दलों के बीच परस्पर विचार की साम्यता भले न हो, पर कोई भी दल देश हित से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा।

देश न तो पहलगाम हमले को भूल सकता है और न सिंदूर के सबक भुलाए जा सकते हैं। सोमवार को लोकसभा में बहस के बाद मंगलवार को राज्यसभा में बहस होगी और फिर जो निचोड़ देश के सामने आएगा, उसका संदेश बहुत सकारात्मक होना चाहिए। दुनिया यह देख रही है या देखना चाहेगी कि भारतीय संसद में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर क्या बात होती है और भारतीय नेता कितने दृढ़ हैं? यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहां तीखे सवाल पूछे जाते हैं और लोगों को स्पष्ट जवाब का इंतजार रहता है। केंद्रीय मंत्रियों को भी जवाब देने का मौका दो बार मिलेगा। कुल मिलाकर, संसद में राजनीतिक एकजुटता और बाहर सुरक्षा बलों का समन्वय अगर सुनिश्चित हो गया, तो भारत के सभी अभियान स्वतः सफल होने लगेंगे।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 29 जुलाई, 1950

## रूस की मांग सही

रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं का गत जनवरी से बहिष्कार किया हुआ था। उसने मांग की थी कि चीन की राष्ट्रवादी सरकार के प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ से हटा दिया जाये और उसके स्थान पर साम्यवादी सरकार को प्रतिनिधित्व दिया जाये। सुरक्षा परिषद ने रूस की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अतः रूस ने सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया। उसकी ओर से कहा गया कि जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं में साम्यवादी चीन को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक वह उनकी बैठकों में हिस्सा नहीं लेगा और उसकी अनुपस्थिति में जो भी निर्णय किये जायेंगे, उन्हें वैध नहीं समझा जायेगा। रूस का बहिष्कार महीनों जारी रहा, किन्तु साम्यवादी चीन को प्रतिनिधित्व देने के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्य विधान के अनुसार आवश्यक संख्या में रजामन्द नहीं हुए। भारत ने साम्यवादी चीन को सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ में लाने का बराबर प्रयास किया, किन्तु उसके प्रयत्नों को निहित स्वार्थों के कारण सफलता नहीं मिली।

संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश की ओर से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार वहां की सरकार को ही हो सकता है। चीन के मामले में राष्ट्रवादी सरकार की सत्ता समाप्त हो गई थी और उसके संचालकों को चीन से हटकर फारमोसा द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था। उसके बाद चीन के थल भाग पर साम्यवादी सरकार शासन कर रही है। अतः वास्तविकता और कानून की दृष्टि से चीन की साम्यवादी सरकार को ही संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हो सकता है। इस बारे में रूस की मांग न्यायोचित थी और जो राष्ट्र साम्यवादी चीन को प्रतिनिधित्व देने का विरोध कर रहे हैं, वे पूर्वाग्रह का ही परिचय दे रहे हैं। साम्यवादी चीन को सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान देने से उसमें रूस की शक्ति बढ़ जायेगी, किन्तु इस आधार पर जो न्यायोचित बात है, उसका विरोध कैसे किया जा सकता है? चीन की राष्ट्रवादी सरकार सत्ता शून्य हो चुकी है और चीन का प्रतिनिधित्व करने का उसका दावा मान्य नहीं किया जा सकता। चीन की राष्ट्रवादी सरकार के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, फिर भी जब उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तो उसके अनुसार भारत को अपना रुख बदलने में संकोच नहीं हुआ।

# मार्क्स को ऐसी श्रद्धांजलि का मतलब

राय की राय

यहां स्कैन करें

विभूति नारायण राय | पूर्व कुलपति व साहित्यकार

**लाबुबू गुड़िया वाली घटना पर इतनी हाय-तौबा क्यों मची? क्या बाजार को समझने के लिए वही औजार आज भी हमारे काम आएंगे, जिन्हें करीब डेढ़ सौ साल पहले मार्क्स ने गढ़ा था?**

उत्तरी लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान के पूर्वी भाग में दफ्न हैं, अपने समय तथा समाज में निर्णायक हस्तक्षेप करने वाले महान समाज वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स, उनकी पत्नी जेनी और उनके परिवार के कई सदस्य। मार्क्स की कब्र पर पिछले दिनों एक चीनी नौजवान ने तीन पृष्ठों का एक दस्तावेज छोड़ा। यह तो कोई खबर नहीं बनती, क्योंकि इस समाधि पर दुनिया भर के लोग कोई कविता, चित्र या आलेख छोड़ते ही रहे हैं, पर खबर बनी लाबुबू नाम की वह गुड़िया, जिसे वह मुसाफिर अपने कागजों के साथ छोड़ गया था।

बाजार कितनी चालाकी से स्मृतियों, पौराणिक आख्यानों और मुनाफे के समीकरण में संतुलन बैठाता है, इसका एक हालिया उदाहरण लाबुबू गुड़िया है। इसके पहले बार्बी डॉल के मामले में यह आजमाया जा चुका था, जब बाजार ने बाल मनोविज्ञान और सौंदर्य-बोध के इस्तेमाल से बार्बी के लिए जबर्दस्त मांग पैदा की थी। लाबुबू गुड़ियों की शुरुआत सबसे पहले हांगकांग में हुई और कलाकार कासिंग लुंग द्वारा रचित नार्डिक परंपरा पर आधारित चित्रों से इनकी उत्पत्ति हुई। लोकप्रिय खिलौना कंपनी पॉप मार्ट ने 2019 में बिक्री के लिए इनका पहला संग्रह तैयार किया, और तब से नए संग्रह जारी होने के साथ-साथ इनके अतिशय लोकप्रिय, महंगे और बिकाऊ संस्करण आते रहते हैं।

जिस कब्रिस्तान में मार्क्स अंतिम विश्राम कर रहे हैं, वह घने वृक्षों से आच्छादित एक विशाल, शांत भूभाग है और किसी शांत जंगल सा एहसास कराता है। एक बार मुझे भी वहां जाने का मौका मिला है। वह एक झीनी बरसात का दिन था और मेट्रो स्टेशन से हल्की फुहारों के बीच मैं अपने दो मित्रों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। सैकड़ों कब्रों के बीच मार्क्स की कब्र कैसे ढूंढेंगे, इसका हल गेट पर ही मिले प्रबंध से जुड़े व्यक्ति ने बताया। हमें अंदर दाखिल होने वाले किसी एक व्यक्ति या समूह के पीछे चलना था, क्योंकि पूरी संभावना थी कि वह मार्क्स की समाधि की तरफ ही जा रहा होगा। सच यही था।

सैकड़ों कब्रों वाले उस कब्रिस्तान में विरला ही कोई मिला, जो अपने किसी अन्य प्रियजन की कब्र पर फूल चढ़ाने जा रहा हो।

मुझे याद है, सोवियत संघ को नष्ट हुए तब पंद्रह वर्ष पूरे हुए थे और मार्क्सवाद के पूरी तरह से समाप्त होने की घोषणा की जा चुकी थी। ऐसे में, वे कौन लोग थे, जो बारिश में भी भीगते हुए मार्क्स की समाधि की ओर बढ़े जा रहे थे? वे दुनिया भर से आए विभिन्न राष्ट्रीयताओं वाले लोग थे। ज्यादातर खाली हाथ थे, पर कुछ के हाथों में पुष्प गुच्छ थे। जब हम उस कब्र के पास पहुंचे, जिस पर कार्ल मार्क्स की एक आवक्ष प्रतिमा थी, उसके चारों तरफ पहले से ही कुछ लोग चुपचाप खड़े थे। माहौल खामोशी में डूबा हुआ था। मौन की भाषा पढ़ी नहीं जा सकती और हम बारिश में भीगते हुए भावनाओं के उस प्रवाह में डूबते-उतराते रहे, जो उस मौन से उपज रहा था।

इस कब्र पर एक आगंतुक जब लाबुबू गुड़िया छोड़कर चला गया, तो मीडिया के मंचों पर इतनी हाय-तौबा क्यों मची? सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ टिप्पणियों की मानें, तो यह एक घटना बाजार के आगे मार्क्स की वैचारिक हार की प्रतीक है। इतनी सरलीकृत व्याख्या से बचते हुए भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि आज का बाजार 19वीं शताब्दी के बाजार से बहुत भिन्न है। अपनी पहुंच, प्रभाव और मानवीय नियति को संचालित करने के सामर्थ्य- हर दृष्टि से। ऐसे में, क्या उसको समझने के लिए वही औजार हमारे काम आएंगे, जिनको लगभग डेढ़ सौ साल पहले मार्क्स ने गढ़ा था?

कल्पना कीजिए, यदि मार्क्स आज सक्रिय होते, तो दुनिया को समझने की जगह उसे बदलने का दावा करने वाले उनके दर्शन की अंतर्वस्तु क्या होती? क्या अभी भी वह सर्वहारा की तानाशाही की बात करते, अभी भी उत्पादन के साधनों पर समाज के सामूहिक नियंत्रण में उनका विश्वास होता या अभी भी एक राष्ट्र-राज्य में सत्ता पर काबिज कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल उनका लक्ष्य होता? जो लोग मानते हैं कि उनका भौतिकवा[illegible] कोई जड़, ठस्स और अपरिवर्तनीय विचार न होक[illegible] द्वंद्वात्मक था, वे यह भी मानेंगे कि मार्क्स के चिंतन [illegible] बदलते सामाजिक यथार्थ के साथ बुनियादी परिवर्त[illegible] भी हुए होते। वे यह देखकर दहशत में पड़ जाते कि सर्वहारा की तानाशाही अंततः पार्टी की तानाशाही औ[illegible] फिर पार्टी नेतृत्व के एक छोटे से गुट की तानाशाही [illegible] बदल जाती है। क्या इसकी जगह वह सर्वहारा के जनतं[illegible] की बात नहीं करते? उस जनतंत्र में क्या एक राष्ट्र[illegible] राज्य में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी होती या वहां एक [illegible] अधिक कम्युनिस्ट पार्टियों की गुंजाइश होती?

मार्क्स जिंदा होते, तो संभवतः पार्टी नेतृत्व से ज[illegible] सी असहमति के चलते किसी को सालों-साल साइबेरिया के ठंडे रेगिस्तान में न बिताने पड़ते। क्या य[illegible] देखकर वह चुप बैठे रहते कि उनकी स्थापनाओं प[illegible] स्थापित समाज में रचनाकारों और बुद्धिजीवियों क[illegible] पार्टी-नेतृत्व की नाराजगी के कारण जेलों में डाल दिय[illegible] जाता है? इस विडंबना पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होत[illegible] कि जीवन भर साम्राज्यवाद और शोषण के खिलाफ लिखने वाले बर्तोल्त ब्रेख्त को जब अपनी जान बचाक[illegible] जर्मनी से भागना पड़ा, तो उन्होंने पूंजीवादी अमेरिक[illegible] को चुना, समाजवादी सोवियत रूस नहीं? क्या वह उ[illegible] कारणों की पड़ताल नहीं करते कि क्यों वियतनाम जैसे युद्धों में फंसा और दुनिया भर में तानाशाहों की मद[illegible] करने वाला अमेरिका ही अपना देश छोड़कर भाग[illegible] वाले कलाकारों और असहमत बुद्धिजीवियों की पहल[illegible] पसंद रहा? सोवियत रूस सोल्जेनित्सिन को प्रताड़ि[illegible] करता रहा और अमेरिका नोम चोमस्की को काम कर[illegible] के लिए विश्वविद्यालयों में स्थान देता रहा। क्य[illegible] सोवियत रूस और चीन के अनुभवों के बाद भी मार्क्स उत्पादन के सारे संसाधनों को राज्य के नियंत्रण में रख[illegible] की सैद्धांतिकी गढ़ते? ये सारे प्रश्न हैं, जिन पर उनके प्रशंसकों को विचार करना होगा।

सारे अंतरविरोधों के बावजूद आज भी मार्क्स दुनिया भर के मुक्तिकामी जन की कल्पनाओं में क्यों बसे हैं? कारण बड़ा स्पष्ट है, दुनिया में गैर-बराबरी औ[illegible] शोषण पहले से बढ़े ही हैं और यदि 19वीं शताब्दी के मार्क्सवादी औजार भोथरे हो गए हैं, तो निश्चित रूप से हमें मनुष्य विरोधी शक्तियों से लड़ने के लिए दूसरी प्रविधि की जरूरत है और मार्क्स आज उसी के अनुरूप अपना नया विमर्श गढ़ रहे होते।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# शतरंज की दुनिया में सबसे नया सितारा दिव्या देशमुख

यहां स्कैन करें

मनोज चतुर्वेदी | वरिष्ठ खेल पत्रकार

दिव्या देशमुख ने मात्र 19 साल की उम्र में जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह भारत के लिए यह खिताब जीतने वाली पहली महिला हैं। दिव्या के लिए यह खिताब इसलिए भी अहम है कि उन्होंने अपने से दोगुनी उम्र की कोनेरू हम्पी को हराकर इसे जीता है। इस खिताबी जीत से वह ग्रैंडमास्टर बनने वाली भारत की चौथी महिला खिलाड़ी बन गई हैं।

इससे पहले यह गौरव उनसे फाइनल में हारने वाली हम्पी, डी हरिका और वैशाली रमेशबाबू को ही हासिल था। अब दिव्या के सामने मुख्य चुनौती कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर विश्व चैंपियन को चुनौती देने का अधिकार हासिल करना होगा। वह यदि विश्व चैंपियन बन जाती हैं, तो भारत के पास पुरुष और महिला वर्ग, दोनों के विश्व चैंपियन हो जाएंगे। अभी कुछ माह पहले ही डी गुकेश ने पुरुष वर्ग में विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच पहली दो बाजियां क्लासिकल शतरंज में बराबर रहने पर टाईब्रेकर में मुकाबला खेला गया, जहां रेपिड बाजियों में दिव्या ने विजय पाकर यह उपलब्धि हासिल की है। दिव्या के लिए रेपिड बाजियों में हम्पी को फतह करने के खास मायने हैं। इसकी वजह यह है कि हम्पी पिछले दिसबंर में ही रेपिड शतरंज की दूसरी बार चैंपियन बनी थीं। वैसे भी वह रैंकिंग में पांचवें स्थान पर हैं और दिव्या तो शीर्ष दस खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं थीं। हालांकि, भारत की इन दो खिलाड़ियों के बीच फाइनल खेले जाने से इस खेल में चीनी दबदबे की कहानी पर भी काफी हद तक विराम लग गया है।

**महिला शतरंज विश्व कप का खिताब जीतने के साथ ही दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की चौथी महिला बन गई हैं।**

यह सही है कि भारत में सही मायनों में शतरंज की अलख जगाने वाले विश्वनाथन आनंद हैं। उन्होंने बोरिस स्पास्की की अगुआई वाले सोवियत संघ (मौजूदा रूस) के दबदबे को तोड़कर भारत को इस खेल में अग्रणी बनाया था। मगर सही मायनों में शतरंज भारतीय दबदबे को डी गुकेश, प्रगनानंद, एरिगेसी की अगुवाई वाली पीढ़ी ने स्थापित किया है। इस तिकड़ी की वजह से पहली बार शतरंज की शीर्ष दस खिलाड़ियों में भारत के चार खिलाड़ी शामिल हुए। अब यह सिलसिला दिव्या के खिताब जीतने से महिला वर्ग में भी शुरू हो गया है। यह सही है कि हम्पी 38 साल की होने की वजह से अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं, पर वैशाली रमेशबाबू दिव्या की तरह ही युवा हैं और यह जोड़ी भी शतरंज में धमाका मचाने की कुव्वत रखती है।

दिव्या के बारे में कहा जाता है कि वह दुर्घटनावश शतरंज खिलाड़ी बनी हैं। उनके हिसाब से उनकी बड़ी बहन बैडमिंटन खेलती थीं और माता-पिता उसके साथ जाते थे। दिव्या उस समय चार-पांच साल की थीं, तो वह भी साथ जाने लगीं, पर उनके बैडमिंटन खेलने में उनका नेट तक भी नहीं पहुंच पाना बाधा बनने लगा। इस कारण उसी हॉल में एक स्थान पर शतरंज होता था, उसे देखने लगीं। शतरंज देखने से उसमें ही मन रम गया और वह शतरंज खिलाड़ी बन गईं। दिव्या के शतरंज में जगे इस शौक को पिता डॉक्टर जितेंद्र और माता नम्रता ने अपने प्रयासों से नई ऊंचाइयां देने में मदद की। उन्होंने नागपुर के अपने निवास के नजदीक एक शतरंज अकादमी में उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया। हमारे यहां कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, दिव्या ने भी मात्र दो साल की कोचिंग में रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह 2012 में पुडुचेरी में राष्ट्रीय शतरंज में अंडर-7 का राष्ट्रीय खिताब जीतने में सफल हो गईं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

दिव्या 2020 आते-आते भारतीय ओलंपियाड टीम की नियमित सदस्य बन गईं और उनकी गिनती देश की दिग्गज खिलाड़ियों में होने लगी। इसका फायदा यह हुआ कि उन्हें नियमित तौर पर विश्वनाथन आनंद की सलाह मिलने लगी। उन्होंने पिछले शतरंज ओलंपियाड में तो व्यक्तिगत बोर्ड का स्वर्ण पदक भी जीता था। बहरहाल, इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्होंने झू जिनेर, तान झोंगयी व द्रोणावल्ली हरिका जैसी दिग्गजों को हराया है। वह जबर्दस्त क्षमता वाली खिलाड़ी हैं। इसलिए यह अप्रत्याशित नहीं है कि लोगों को उनसे यह उम्मीद थी और उन्होंने यह करके दिखा दिया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

# यथार्थ को कैसे समझें

हम अतीत का परिणाम हैं। हमारे विचार बीते कल और हजारों बीते दिनों पर आधारित हैं। हम समय का परिणाम हैं; हमारे प्रत्युत्तर व वर्तमान तौर-तरीके हजारों क्षणों, घटनाओं और अनुभवों का संचयी परिणाम हैं। अतः हममें से अधिकांश के लिए अतीत ही वर्तमान है और यह एक ऐसा तथ्य है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप, आपके विचार, आपके कर्म, आपके प्रत्युत्तर अतीत के परिणाम हैं।

यहां सवाल उठता है कि क्या उस अतीत को तत्काल पोंछा जा सकता है, अर्थात समय के दायरे में नहीं, बल्कि तत्क्षण; या इस संचयी अतीत से वर्तमान में मुक्त होने के लिए मन को समय की दरकार होती है? इस प्रश्न को समझ लेना आवश्यक है। प्रश्न यह है- चूंकि हममें से हर कोई अतीत का परिणाम है, अगणित प्रभावों से निर्मित उसकी एक पृष्ठभूमि है, जो निरंतर परिवर्तनशील है, तो क्या समय की प्रक्रिया से गुजरे बिना इस पृष्ठभूमि को पोंछ डालना संभव है?

यह अतीत क्या है? अतीत से हमारा क्या तात्पर्य है? निस्संदेह, उससे हमारा तात्पर्य क्रमागत, ऐतिहासिक अतीत से नहीं, अपितु संचित अनुभवों, संचित अनुक्रियाओं, स्मृतियों, परंपराओं और ज्ञान से है; अगणित विचारों, भावनाओं, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के अवचेतन भंडार से है। अतीत की इस पृष्ठभूमि के रहते यथार्थ को समझना संभव नहीं है, क्योंकि यथार्थ का समय से क्या संबंध! यह तो कालातीत है, समय से परे है। मन जो स्वयं काल की उपज है, उससे हम कालातीत को नहीं समझ सकते। लोग जानना चाहते हैं कि क्या मन को मुक्त करना संभव है, अथवा मन जो समय का परिणाम है, क्या उसके लिए यह संभव है कि उसका तत्क्षण अवसान हो जाए? अथवा, क्या यह जरूरी है कि व्यक्ति परीक्षाओं और विश्लेषणों की एक लंबी शृंखला से गुजरे और इस प्रकार धीरे-धीरे मन को इसकी पृष्ठभूमि से मुक्त कर ले?

अनेक विश्लेषक कहते हैं कि इस पृष्ठभूमि से मुक्त होने के लिए हर प्रतिक्रिया, हर जटिलता, हर बाधा, हर अवरोध की छानबीन जरूरी है, जिसका स्पष्ट निहितार्थ समय की प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि विश्लेषक के

**अतीत की पृष्ठभूमि के रहते यथार्थ को समझना संभव नहीं है, क्योंकि यथार्थ कालातीत है, समय से परे है। मन जो स्वयं काल की उपज है, उससे हम कालातीत को नहीं समझ सकते।**

लिए यह समझना जरूरी है कि वह किसका विश्लेषण कर रहा है और यह भी जरूरी है कि अपने विश्लेषण में वह उसका गलत अर्थ न निकाले। यदि वह ऐसा करता है, तो वह गलत निष्कर्षों पर पहुंचेगा और इस प्रकार एक दूसरी पृष्ठभूमि स्थापित कर लेगा। जरा भी इधर-उधर न हटकर अपने विचारों तथा भावनाओं का विश्लेषण करने की क्षमता विश्लेषक में होनी चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम उठाने का मतलब है, किसी दूसरे स्तर पर दोबारा एक अन्य पृष्ठभूमि को स्थापित करना।

जे कृष्णमूर्ति

शेखर कपूर | फिल्म निर्देशक

**अक्षय ऊर्जा की धारा को रोका नहीं जा सकता। आइए, एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हो, बल्कि न्यायसंगत भी हो; जो न सिर्फ तेज, बल्कि निष्पक्ष भी हो; जो न केवल परिवर्तनकारी, बल्कि समावेशी भी हो।**

# यह सीबीएसई का तुगलकी फरमान

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सुझाव पर सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने का जो निर्देश जारी किया है, वह जोर-जबर्दस्ती वाला निर्देश है। इससे सीबीएसई स्कूलों पर सरकार की जकड़ जकड़न में बदल जाएगी और अपनी जरूरत के हिसाब से किताबें पढ़ाने की उनकी आजादी छिन जाएगी।

अभी तक एनसीईआरटी की किताबों को नौवीं कक्षा से अनिवार्य किया गया था और पहली से आठवीं क्लास तक इससे छूट मिली हुई थी। गौरतलब है कि एनसीईआरटी ने सरकार के निर्देश पर अपनी किताबों में बहुत से विवादास्पद बदलाव किए हैं, खासकर इतिहास की किताबों में तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने का आरोप लगा है, जिनमें प्रमुख तौर पर मुगलों का इतिहास है। सवाल यह है कि एनसीईआरटी की किताबों को आठवीं तक न पढ़ाने की मिली छूट आखिर वापस क्यों ली गई? दरअसल, इसे शिक्षा व्यवस्था पर एक खास विचारधारा को लादने की साजिश का हिस्सा माना जाना चाहिए। दिलचस्प यह है कि सीबीएसई ने इसके बारे में अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी, पर उस समय एनसीईआरटी की आठवीं तक की सभी विषयों की पुस्तकों के बाजार में न आने से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि चूंकि एनसीईआरटी की आठवीं तक की सभी पुस्तकें आ गई हैं, तो सीबीएसई ने स्कूलों को इस पर अमल का निर्देश दिया है, जो अलोकतांत्रिक हैं।

वास्तव में, सीबीएसई पर सरकार का जैसा नियंत्रण है, वह सही नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि अलग-अलग राज्य में बच्चों को विशेष तौर पर समाज विज्ञान की पुस्तकों में स्थानीय जानकारियां भी देनी होती हैं, जो एनसीईआरटी की किताबों में नहीं दी जा सकतीं, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जाती है। जाहिर है, सीबीएसई का नया आदेश तानाशाही भरा है, क्योंकि यह एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास है और समाज के बाकी वर्गों की सोच को दबाने की एक चाल। वैसे भी, एनसीईआरटी आजकल न तो समय पर अपनी किताबें छाप पा रहा है और न ही बाजार में उपलब्ध करा पा रहा है। ऐसे में, सीबीएसई को अपना यह तुगलकी फरमान फौरन वापस लेना चाहिए और पाठ्यक्रम व किताबों के मामले में स्कूलों की स्वायत्तता पर हमला नहीं करना चाहिए। सीबीएसई को इसको मान्यता देने की शर्त भी नहीं बनाना चाहिए। फिर भी, वह यदि ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ बिना हिचक अदालत का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए।

सामी अहमद, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

पाठ्यक्रम बदलाव

# इस फैसले की सराहना होनी चाहिए

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नया आदेश कि सभी विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी, बहुत सही फैसला है। इसकी भरपूर सराहना की जानी चाहिए। इस निर्णय से छात्र-छात्राओं के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी बड़ी राहत महसूस हो रही होगी, क्योंकि निजी प्रकाशकों की पुस्तकें, एनसीईआरटी की किताबों के मुकाबले बहुत महंगी होती हैं। एक तो निजी स्कूलों की फीस सुरसा के मुंह जैसी हर साल बढ़ती ही जाती है, उस पर से उनके पब्लिकेशन की पुस्तकें आग में घी डालने का काम करती हैं। वे काफी महंगी होती हैं और अभिभावकों के बजट को काफी अधिक प्रभावित करती हैं। इस नए निर्देश के बाद तमाम अभिभावकों को चैन की सांस आई होगी कि अब उन्हें महंगी पुस्तकें नहीं खरीदनी होंगी। आगे चलकर, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें ही बच्चों के काम आएंगी, तो कक्षा एक से ही इसकी पढ़ाई क्यों न कराई जाए? इससे बच्चों के भविष्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इस निर्णय से छात्रों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि शुरुआत से ही एनसीईआरटी की किताबों के पढ़ने से उनकी बुनियाद अधिक मजबूत होगी। अब यह निश्चित करना जरूरी है कि सभी निजी स्कूल इस आदेश का पालन करें। जो ऐसा नहीं करते हैं, उनको दंडित करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

यह एक अच्छी खबर है कि सीबीएसई स्कूलों में अब पहली कक्षा से ही एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। इसको लेकर जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और स्कूलों को कहा गया है कि अब पहली से आठवीं कक्षा तक भी वे एनसीईआरटी की किताबें ही बच्चों को पढ़ाएं। इससे खासा लाभ मिलेगा। एक तो निजी स्कूलों द्वारा पुस्तकों के नाम पर ऐंठी जा रही मोटी रकम से अभिभावकों को राहत मिल सकेगी, क्योंकि अभी तक होता यही था कि स्कूल जबरिया अपने खास पब्लिकेशन हाउस की किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए बाध्य करते थे, जो काफी महंगी होती थीं। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। फिर, नई शिक्षा नीति के अनुसार इससे देश भर में पाठ्यक्रम में समानता आएगी और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। इससे पठन-पाठन में मौजूद असमानता से भी पार पाना आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर, एक ऐसा निर्देश जारी किया गया है, जो छात्र-छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए कारगर साबित हो सकता है। अब जरूरत इसे तमाम स्कूलों में सख्ती से लागू करने की है।

दीपाली कुमारी, टिप्पणीकार

चिंतन

# जवाब सुनने का धैर्य रखे विपक्ष, केवल हंगामा न करे

संसद सत्र के दौरान विपक्ष अगर किसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है और किसी प्रश्न का जवाब चाहता है तो उसमें सुनने का धैर्य भी होना चाहिए और सरकार से मिले जवाब पर भरोसा भी करना चाहिए। सवालों के जरिये यदि विपक्ष की मंशा संसद में हंगामा कर ठप करने की है और मकसद केवल राजनीति करना है, तो फिर वो अपनी संसदीय भूमिका नहीं निभा रहा है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के दिन से कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के सभी विपक्षी दल पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम करने के दावे, मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण आदि मुद्दों पर चर्चा की मांग करते रहे हैं। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष को आश्वासन दिया कि वह सभी मुद्दों पर नियम के दायरे में चर्चा के लिए तैयार है। अब सरकार अगर संसद में विपक्ष के प्रश्नों के संदर्भ में सिलसिलेवार जवाब दे रही है, तो विपक्ष न सुनने समझने के लिए तैयार है न ही यकीन करने करने को राजी है। लगता है कांग्रेस ने एक ही ध्येय बना लिया है कि येनकेन प्रकार संसद में हंगामा करना है और सत्र नहीं चलने देना है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि सोमवार को जब संसद में कांग्रेस ने तीखे सवाल किए तो सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृहमंत्री अमित शाह ने बारी बारी से जवाब दिए, लेकिन इस दौरान कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के विपक्षी नेता हंगामा व नारेबाजी करते रहे। विपक्ष ने सरकार से जो सवाल पूछे हैं कि 100 दिन बीतने के बाद भी पहलगाम हमले के आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रोका गया, भारत व पाक के बीच संघर्ष विराम को लेकर ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई है और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा? आदि स्वाभाविक व जायज सवाल हैं, लेकिन विपक्षियों को सरकार का जवाब भी सुनना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। विपक्ष के सांसद भी भारत के ही हैं और वे इसी देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनका दृष्टिकोण भी राष्ट्रीय होना चाहिए। उनके सवाल पूछने व उठाने के तरीकों से लगता है कि जैसे वे भारत के सांसद ही न हों। पुलवामा व उरी हमले के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक के दौरान में कांग्रेस राष्ट्रीय हद से पार जाकर अपनी ही सेना की क्षमता को कटघरे में खड़ा कर रही थी। कम से कम सैन्य ऑपरेशन व कूटनीति-विदेश नीति के मसले पर तो देश में पचास से अधिक वर्ष शासन करने वाली कांग्रेस को तो राष्ट्रीय समझ के साथ सवाल उठाने चाहिए और आरोप लगाने चाहिए। संसद में सरकार ने साफ जवाब दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सफल सैन्य एक्शन था, आतंकियों को सबक सिखाया गया, पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब दिया गया, श्भारत व पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में राष्ट्रपति ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई, तो विपक्ष को जवाब पर भरोसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ट्रंप का दावा महज दावा ही है। हालांकि अभी तक पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार पांच दहशतगर्दों का नहीं पकड़ा जाना पीड़ितों को न्याय की बाधा है। कांग्रेस को सैन्य मसलों पर राजनीति छोड़ राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए। संसद में हंगामा कर उसे ठप नहीं किया जाना चाहिए।

एनईपी के 5 वर्ष

डॉ. ऐश्वर्या झा

# शिक्षा क्षेत्र की कायापलट की जरूरत

शिक्षा हमेशा से मानव विकास, विकसित राष्ट्र एवं सामाजिक प्रगति के लिए आधारशिला मानी गई है। शिक्षा केवल धन उपार्जन, रोजगार सृजन, तथ्यों का संग्रह या आँकड़ों को याद रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक गहन बहुआयामी प्रक्रिया है जो व्यक्ति एवं मानव समाज के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास को आकार देती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सफल और संपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक उपकरण प्राप्त करता है। शिक्षा प्रणाली ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। प्राचीन भारत में शिक्षा, आध्यात्मिकता और आत्म-साक्षात्कार पर केंद्रित थी। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना और उनका विस्तार करना था। शिक्षा गुरुकुलों, आश्रमों, धार्मिक स्थानों और घरों में दी जाती थी। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में शिक्षा का सबसे पुराने विश्वविद्यालय माने जाते रहे हैं।

किसी भी देश में शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए नीति की जरूरत होती है। गुलाम मानसिकता के प्रतीक मैकाले की शिक्षा पद्धति को परिवर्तित करने के उद्देश्य से कोठारी आयोग (1964-1966) के अनुशंसा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में पहली बार लागू और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। 29 जुलाई, 2020 को 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' द्वारा के कस्तूरीरंगन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई, जिसमें समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिया है एवं इस वर्ष इस नीति के पांच वर्ष पूरे हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। 34 वर्ष के अंतराल पर आई यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली के ढाँचे में तीसरा बड़ा सुधार है, जिसके माध्यम से रटंत आधारित शिक्षण, पाठ्यक्रम का अत्यधिक बोझ, निम्न शिक्षण परिणाम, उच्च शिक्षा पहुँच में असमानता और अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण जैसी समस्या का समाधान सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति चार स्तरों - स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, और व्यावसायिक एवं प्रौढ़ शिक्षा - में शैक्षिक ढाँचे को पुनर्परिभाषित करती है। इसका लक्ष्य उच्च शिक्षा सहित संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाना है, जहां बहु-विषयक शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। इस नीति के माध्यम से स्कूली पाठ्यक्रम में 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया गया है जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 उम्र वर्ग के बच्चों के लिए है, पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से आदि कई बदलाव किये गए है। स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर, माध्यमिक स्तर तक सभी को शिक्षा, स्कूल से दूर रह रहे दो करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा, उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें, शिक्षक-

विद्यार्थी अनुपात स्कूल में 30:1 (सामाजिक - आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में 25:1), ईआईटी, आईआईएम की तर्ज पर ही समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) विकसित करने, दीक्षा पोर्टल पर चुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक जगह संकलित कर डिजिटल माध्यम से सभी छात्रों को उपलब्ध करवाने, 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना एवं 2040 तक सभी शिक्षार्थियों के लिये गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देना है। इस नीति में मूल्यांकन का अभिनव प्रयोग "परख" (PARAKH = Performance, Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development) है जो समग्र विकास हेतु ज्ञान की समीक्षा और विश्लेषण करती है।

अधिकांश राज्यों ने नई 5+3+3+4 संरचना, आधारभूत संरचना, शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल सामग्री व मातृभाषा में शिक्षा, त्रिभाषा जैसे बिंदुओं पर क्रियान्वयन की दिशा में तेज प्रगति की है। इन पांच वर्षों में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों ने विश्वविद्यालय कॉलेजों की संख्या, जीईआर, छात्र-शिक्षक अनुपात, लैंगिक समानता अनुपात जैसे प्रमुख मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन किया है किंतु यह शिक्षा नीति के लक्षित दर से आधा भी नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विगत दस वर्षों में संस्थानों की संख्या में 13.8% की वृद्धि, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 28.4% एवं यह वृद्धि बेहतर बुनियादी ढाँचे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी नीतियों के बजह हुई है।

शिक्षा नीति के पूर्ण कार्यान्वयन में कुछ बाधाएं हैं। इसके शुरुआती कार्यान्वयन एवं प्रगति में कोरोना महामारी के कारण देरी हुई। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक चर्चा का अभाव एवं उसकी गलत व्याख्या और उदासीनता भी इसकी प्रगति में बाधक बनी। इन पाँच वर्षों में एनईपी के भाषा सूत्र को लेकर भ्रम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषिकता को स्थानिक शिक्षा प्रणाली में अपनाने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चौथे तथा 22वें अध्याय में बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति पर बात की गई है जिसमें मातृभाषा की अनिवार्यता को स्वीकार कर उसमें शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट किया गया है। राजनीतिक कारण हिंदी की तथाकथित प्रमुखता को आए दिन विवाद का मुद्दा बनाते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु में हुआ विरोध इसका उदाहरण है। विश्वविद्यालयों में निजीकरण को लेकर भी संदेह की स्थिति है, जबकि एनईपी सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने पर जोर देती है। शैक्षिक नीतियों का सफल कार्यान्वयन कई महत्त्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है। एनईपी केवल परामर्शात्मक प्रकृति का है। कुछ राज्यों ने एनईपी से संबंधित कुछ मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। हिमाचल प्रदेश एनईपी को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य था, वहीं पांच वर्ष उपरांत भी कम से कम तीन राज्यों ने भी कार्यान्वयन के लिए सहमति नहीं दी है। भारत अपनी जीडीपी का लगभग 3-4% शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि शिक्षा नीति के लक्ष्य 6 % से कम है। भारत में शिक्षा पर खर्च, भूटान और मालदीव जैसे अन्य पड़ोसी देशों से भी कम है। नीति को विनियमित करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का प्रस्ताव था जिसका गठन वर्तमान निकायों यूजीसी, एआइसीटीई आदि का विलय करके किया जाना चार वर्ष बाद भी लंबित है एवं 2025 के मानसून सत्र में शायद ही पारित हो। देश भर में विभिन्न संस्थानों में पिछले कई वर्षों से शिक्षक की कमी चिंता का विषय है। एनईपी को लागू करने के साथ शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश की जरूरत है, ताकि कायाकल्प हो।

(लेखिका एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र बहुलाल लॉलेज, रोहतक, हरियाणा में कार्यरत हैं। लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।)

उपलब्धि

डॉ. अश्वनी महाजन

# भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश

हाल ही में जारी विश्व बैंक की 'सप्रिंग 2025 पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ' ने दुनिया में एक बहस शुरू की है। बहस का मुद्दा यह है कि क्या भारत असमानता में दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है, जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है? वास्तव में देश और दुनिया में प्रचलित विमर्श का यह रिपोर्ट खंडन करती है। देश में बड़ी तादाद में बुद्धिजीवी जो इससे पूर्व की रिपोर्टों और आंकड़ों का हवाला देते हुए यह तर्क देते रहे हैं कि देश में आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ असमानताएं भी बढ़ी हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ी है, वंचित वर्ग के हालात पहले से अधिक बिगड़े हैं और यह असमानता आय और संपत्ति दोनों में दिखाई देती है। ऐसे में यदि कोई रिपोर्ट यह कहे कि देश में असमानताएं कम हुई है तो असमंजस स्वाभाविक ही है। ऐसे में उन बुद्धिजीवियों द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट पर प्रश्नचिन्ह लगाना भी स्वाभाविक ही है। लेकिन यहां यह भी सत्य है कि जो लोग यह मानते हैं कि देश में आय और संपत्ति की असमानताएं बढ़ी है, वे भी आंकड़ों के आधार पर अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं और जो रिपोर्ट विश्व बैंक ने प्रकाशित की है, वह भी आंकड़ों पर ही आधारित है। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल है, जैसा इसके आलोचक दावा करते हैं या उसमें कुछ सच्चाई है। और यदि यह सच है तो यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में समानताएं घटने के पीछे कारण क्या हैं ?

असमानताओं को मापने का सर्वाधिक उपयोगी तरीका गिनी चटॉक माना जाता है। गिनी चटॉक शून्य से एक तक होता है, जहां शून्य गिनी सह गुणांक पूर्णतः समानता को और 1 पूर्णतः असमानता को दर्शाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च और अन्य गृहस्थ आय सर्वेक्षणों के आंकड़ों के अनुसार 2023 में आय गिनी सह गुणांक 0.410 था जो 1955 में 0.371 से भी अधिक था। यदि संपत्ति के वितरण के बारे में विचार करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2023 में यह सह गुणांक 0.405 था जो 1955 में 0.341 से कहीं अधिक था जबकि शहरी क्षेत्र में यह 1955 में 0.392 से घटकर 2023 में 0.382 ही रह गया लेकिन अभी भी यह काफी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। भारत में आय और संपत्ति में बढ़ती असमानताओं के बीच, अच्छी खबर यह है कि उपभोग में असमानताएँ कम हो रही हैं। इसे अलग-अलग शब्दों में पहले यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में भारी कमी और बाद में विश्व बैंक की हाल ही में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में अत्यधिक गरीबी में बड़ी कमी दर्ज की गई है। हालाँकि अत्यधिक गरीबी की परिभाषा 2.15 डॉलर प्रतिदिन से बदलकर 3.0 डॉलर प्रतिदिन कर दी गई है, फिर भी 2022-23 में केवल 5.3 प्रतिशत लोग ही अत्यधिक गरीबी से पीड़ित थे। दिलचस्प बात यह है कि 2011-12 में यह आँकड़ा 27.1 प्रतिशत था। और यदि इस परिभाषा को पहले की तरह 2.15 डॉलर ही रखा जाए, तो 2022-23 में अत्यधिक गरीबी से पीड़ित लोगों का प्रतिशत केवल 2.3 प्रतिशत ही रह गया है। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में उपभोग में असमानताएँ अब कम हो गई हैं। एक अधिक समतापूर्ण समाज की ओर भारत की यात्रा पिछले कुछ वर्षों में उसके गिनी सूचकांक में परिलक्षित होती है। 2011 में यह सूचकांक 28.8 था, जो 2022 में 25.5 तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि अब यूएनडीपी से लेकर विश्व बैंक तक, सब में इस बात पर आम सहमति है कि भारत में उपभोग असमानताएं निश्चित रूप से कम हुई हैं। लेकिन दूसरी ओर आलोचक भारत में बढ़ती असमानताओं का तर्क आगे बढ़ा रहे हैं, वे इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि गरीबी और उपभोग में समानताएं दोनों पहले से कम हो गए हैं।

आलोचकों का पहला तर्क यह है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है और इसमें आय और संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है। उपभोग आधारित गिनी सहगुणांक असमानताओं को कम करके आंकता है, क्योंकि अमीर लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचा लेते हैं। उसके मुकाबले आय आधारित समानताएं अधिक विस्तृत अवधारणा है और उस संदर्भ में भारत में आय और संपत्ति की असमानताएं वास्तव में बढ़ी हैं। आलोचकों का दूसरा तर्क यह है कि विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया गया सर्वेक्षण उपभोग को ठीक प्रकार से आकलन नहीं कर पाया। ऊपर के पांच प्रतिशत अमीर सामान्य सर्वेक्षण में अपने उपभोग को कम कर बताते हैं और उसे आधार पर निष्कर्ष सही नहीं होगा।

(लेखक पूर्व प्रोफेसर, पीजीडीएवी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

## उद्यमो भैरवः

संकलित

दर्शन

हम इस दार्शनिक उलझन में पड़ गए हैं कि प्रभु करते हैं या हम करते हैं। क्या मैंने भी कुछ किया है या सबकुछ प्रभु ही कराते हैं? इसको समझना बहुत आवश्यक है। इस बात को समझे बिना, आध्यात्म के नाम पर हम क्या-क्या करते हैं। इसलिए, तथाकथित धार्मिक या आध्यात्मिक लोग बहुत समस्या पैदा करते हैं। स्वयं भी समस्या में उलझ जाते हैं और दूसरों के लिए भी समस्या पैदा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अकर्मण्यता पकड़ लेती है। एक चिलक्षण शिव सूत्र है, 'उद्यमो भैरव:' भैरव शिव जी से ही प्रकट हुई शक्ति है। यदि आप किसी कार्य में संलग्न हैं तो उसमें अपना सौ प्रतिशत लगाएं। यही उद्यम है। ये आपको मुक्त कर देगा। जो काम करना है, उसके बारे में सोचकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। करना है और छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो वह भी नहीं होगा। जो करना है, वह पूरा करके समाप्त करें और जो छोड़ना है, उसे छोड़कर शांत हो जाएं। दोनों में सौ प्रतिशत लगाएं। उद्यमो भैरव: प्रयत्न भी भगवान ही है। यदि हमारे उद्यम से ही सारा लाभ प्राप्त हो जाए तो हर एक व्यक्ति सफल हो जाता। ऐसा तो नहीं होता है। जब आप कोई काम करते हैं तो कभी सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं। एक आलसी व्यक्ति सब छोड़कर बैठ जाता है। जब होगा, तब होगा। और जो व्यक्ति ज्वर से पीड़ित है, वह करता ही जा रहा है। वह तनाव से भरा हुआ है। वह आशाओं के पत्थरों को सिर पर ढो रहा है। उसके भीतर विभिन्न प्रकार की नकारात्मक संवेदनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो मार्ग क्या है? कहां है? तब बताते हैं, 'उद्यमो भैरव:'।

## अर्जुन को अपनी विद्या पर था घमंड

संकलित

प्रेरणा

महाभारत का प्रसंग है। कौरव और पांडवों का युद्ध तय हो गया था। दोनों ही पक्ष युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। उस समय अर्जुन ने एक पर्वत पर देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र पाने के लिए तप किया। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मुझसे दिव्यास्त्र लेने से पहले तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा। इंद्र देव की बात मानकर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने तप शुरू कर दिया। जिस जगह अर्जुन तप कर रहे थे, वहां एक दिन एक जंगली सूअर आ गया। सूअर एक मायावी दैत्य था। अर्जुन ने जैसे ही जंगली सूअर को देखा, उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तभी वहां किरात वनवासी पहुंच गया। किरात वनवासी कोई और नहीं, बल्कि शिवजी ही थे, जो वेष बदलकर आए थे। वनवासी ने अर्जुन को बाण चलाने से रोक दिया और कहा कि ये मेरा शिकार है। ये बात सुनने के बाद भी अर्जुन ने तीर सूअर की ओर छोड़ दिया। वनवासी ने भी उसी समय बाण छोड़ दिया। अर्जुन और वनवासी के बाण एक साथ उस सूअर को लगे। सूअर तो मर गया, लेकिन इस दोनों के बीच विवाद होने लगा। ये विवाद युद्ध तक पहुंच गया। युद्ध के बीच में वनवासी ने एक बाण अर्जुन को लग गया। इसके बाद अर्जुन ने कुछ देर के लिए युद्ध रोका और मिट्टी का एक शिवलिंग पूजा की। पूजा में जो माला अर्जुन ने शिवलिंग पर चढ़ाई थी, वह उस वनवासी के गले में दिखाई देने लगी। ये देखकर अर्जुन समझ गए कि ये स्वयं शिव जी ही हैं।

## अंतर्मन

## आज की पाती

### बीमा सखी योजना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

केंद्र सरकार की बीमा सखी योजना न केवल महिलाओं के लिए उपयोगी होगी, बल्कि ग्रामीण भारत को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण है। किसानों लिए सरकार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं हैं, बल्कि गांधी मे बीमा सखी योजना आर्थिक सुधारों के लिए मिल का पत्थर साबित हुई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि किसान एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि मोदी के नेतृत्व में बीमा सखी योजना महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। केंद और राज्य सरकार की अनेक योजना महिला सशक्तिकरण की तरफ विकास की बुलंदियां छूने के लिए पर्याप्त है।

-कांतिलाल मांडोत, सूरत

## ट्रेंड

### बहुत-बहुत बधाई

दिया टेताशु को जेरी स्टॉरिक कार्ड, जो महिला विश्व कप जीतने वाली पहली आदिवासी महिला क्रिकेटर बनीं, मात्र उन्नीस वर्ष की आयु में। उन्होंने हमारी उपजीविका रही और तकरीबन हिप रिप्लेसमेंटवाला वर्ष दोनों पाइपलाइन में आता से तीं।

-दौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

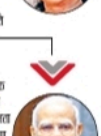

### महानता के दर्शन

रौद्र सिद्धांत और छोल गर्टिट कल्चर' नामक एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी देखी, जो तमिल इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक महानता को दर्शाती है। यह देखने के बाद ऐसा लगा कि हमारी संस्कृति से हमें कितनी अद्भुत सौगात दी है। जो दुनियाभर को जोल जोल के संस्कार दे रही है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

### आपका बहुत अभिनंदन

आलीशा के विरुद्ध उठा साहसपूर्ण आरोप अविश्वास एक गुप्त पीड़ा, देशद्रोह व संस्कृति की रक्षा के महत्वपूर्ण योगदान होना, यह लड़ाई लोकतंत्र व अखंडता की है, आलीशा व लोकतंत्र के विरुद्ध महत्वपूर्ण हिंसक के लिए आपका बहुत अभिनंदन।

- बाबा रामदेव, योगगुरु

### खाना लाजवाब

हाल ही में, व्यतीर्थी ने कैसे घर का स्वाद चखा। उस वादर में, जो कभी खोज नहीं, मुझे लखते अच्छा लहरीय रेस्तरां मिला जहां छत डिजिन के सामने छत प्लेट में सब हुए नजर आए। खाना तो बहुत लाजवाब था।

- अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड,
रोहतक-124001 फोन: 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

## करंट अफेयर

# किम की बहन ने द. कोरिया की सुलह पहल को ठुकराया

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन ने दक्षिण कोरिया की नयी सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें उसने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए बातचीत की पेशकश की थी।

किम जोंग की बहन ने इस प्रस्ताव को सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत करने में कोई रुचि नहीं है, चाहे उसका प्रतिद्वंद्वी कोई भी प्रस्ताव क्यों न पेश करे। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग की इन टिप्पणियों से फिर से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर कोरिया का निवट भविष्य में दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की कूटनीतिक बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। उत्तर कोरिया इस समय रूस के साथ अपने बढ़ते रक्षयोग पर अधिक ध्यान दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि उत्तर कोरिया को लगता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के बाद भी वह रूस के साथ अपने संबंधों को पहले जैसा नहीं रख पाएगा, तो वह अपना रुख बदल सकता है। दक्षिण कोरिया के सरकारी मीडिया द्वारा जारी एक बयान में किम यो जोंग ने कहा, ''हम एक बार फिर आधिकारिक रुख स्पष्ट करते हैं कि सियोल (दक्षिण कोरिया) में चाहे कोई भी नीति अपनाई जाए और कोई भी प्रस्ताव रखा जाए, हमें उसमें कोई रुचि नहीं है।

## ऑफ बीट

# हरित ऊर्जा के लिए पृथ्वी पर पर्याप्त हाइड्रोजन मौजूद

पृथ्वी की महाद्वीपीय चट्टानों के स्वरसे पुराने हिस्सों ने अरबों वर्षों से बड़े पैमाने पर प्राकृतिक हाइड्रोजन उत्पन्न किया है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गैस

पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद भंडारों में संचित हो सकती है, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थायी स्रोत बन सकती है। माली में एक गैस क्षेत्र से शुद्ध प्राकृतिक हाइड्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन इसकी व्यापक संभावनाओं का प्रमाण है, जिसने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोप के नीति-निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है। तेजी से बढ़ रही रुचि सन 2023 के अंत तक दुनियाभर में 40 कंपनियां प्राकृतिक हाइड्रोजन की खोज में सक्रिय थीं और वर्ष 2024 से यह संख्या दोगुनी होने की संभावना जताई गई है। इसमें औद्योगिक निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय खनिज कंपनियों की भागीदारी भी बढ़ी है तथा आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में नयावार की भी संभावना है। हाइड्रोजन : एक बहुपयोगी संसाधन ईंधन परिष्करण, अमोनिया और उर्वरक उत्पादन तथा इस्पात उद्योग जैसे क्षेत्रों में पहले से ही हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है। ब्रिटेन सरकार के एक हालिया नीति पत्र के अनुसार, हाइड्रोजन को प्राकृतिक संसाधन के रूप में मान्यता दिए बिना इस क्षेत्र में निवेश और विकास को बढ़ावा देना मुश्किल है।

दैनिक जागरण
पाप का अंत निश्चित होता है

# गाजा संकट पर मूकदर्शक मोदी सरकार

सोनिया गांधी

**पीएम मोदी स्पष्ट और साहसिक शब्दों में उस विरासत की ओर से जोरदार आवाज उठाएं, जिसका प्रतिनिधित्व भारत लंबे समय से करता आया है**

प्रतीक राजपूत

7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर हमास द्वारा किए गए बर्बर हमलों या उसके बाद इजरायली लोगों को लगातार बंधक बनाए रखने को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। इसकी बार-बार और बिना किसी शर्त निंदा की जानी चाहिए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य और उसमें भी बढ़कर एक ईसान होने के नाते यह स्वीकारना हमारी जिम्मेदारी है कि गाजा की जनता पर इजरायली सरकार की प्रतिक्रिया और प्रतिशोध ने केवल उग्र रहा है, बल्कि यह पूरी तरह आपराधिक भी है। पिछले लगभग दो वर्षों में 55,000 से अधिक फलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 17,000 बच्चे शामिल हैं। गाजा में अधिकांश आवासीय इमारतों को जानबूझकर लगातार हवाई बमबारी के जरिये पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। इनमें अस्पताल भी शामिल हैं। वहां का सामाजिक ढांचा पूरी तरह बिखर चुका है। अक्टूबर 2023 से अब तक की घटनाएं परेशान करने वाली रही हैं। हाल के महीनों में स्थिति और हृदयविदारक हो गई है। हमने देखा है कि किस तरह मानवीय सहायता को भी एक नृशंस रणनीति के तहत हथियार बना दिया गया है। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा की सैन्य नाकेबंदी कर वहां दवाओं, भोजन और ईंधन की आपूर्ति को क्रूर नीयत से बाधित किया है। वहां के चुनिंदा ढांचे का अंधाधुंध विनाश और आम नागरिकों का बेतरतीब नरसंहार एक मानव निर्मित त्रासदी को जन्म दे चुका है। नाकेबंदी ने इसी और भी भयावह बना दिया है। भूख से मरने की मजबूर करने की रणनीति मानवता के खिलाफ अपराध है। इस तबाही के बीच इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों से आने वाली मानवीय सहायता या तो सिरे से नकार दी है या उसे रोक दिया है। इंसानियत के हर विचार को विकृत करते हुए इजरायली सैनिकों ने उन लोगों पर बेरहमी से गोलियां बरसाईं, जो परिवारों के लिए भोजन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। इजरायली रक्षा बलों की भी इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा है।

गाजा में इजरायल के कैम्प कब्जे को लेकर विरोधियों के लगभग सभी आकलनों के अनुसार यह एक ऐसा अभियान है, जिसका प्रभाव जनसंहार जैसा है और जिसका उद्देश्य गाजा पट्टी से फलस्तीनियों का नस्लीय सफाया करना है। इसका पैमाने और परिणाम 1948 की 'नकबा' त्रासदी की याद दिलाता है, जिसमें फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल किया गया। यह क्रूरता कुछ सबसे घिनौने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जा रही है। इनमें औपनिवेशिक मानसिकता से लैस कुछ लालची रियल एस्टेट कारोबारियों के स्वार्थ भी शामिल हैं। दुर्भाग्य से गाजा संकट ने वैश्विक व्यवस्था की सबसे गंभीर कमजोरियों को उजागर कर दिया है। गाजा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम की मांग करने वाले सूरन महासभा के प्रस्तावों को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया। सुरक्षा परिषद गाजा में आम नागरिकों पर किए जा रहे हमलों और उनके बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर किए जा रहे विनाश के लिए भी इजरायली सरकार पर प्रतिबंध लगाने में विफल रही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 26 जनवरी, 2024 को इजरायल को जनसंहार जैसे कृत्य रोकने और नागरिकों तक आवश्यक सेवाएं तथा मानवीय सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए थे। इन्हें भी अनदेखा किया गया। अमेरिका से मिले प्रत्यक्ष-परोक्ष समर्थन ने न केवल इजरायल को इन कार्रवाइयों के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उन्हें संभव भी बनाया। जब अंतरराष्ट्रीय कानून और संस्थाएं लगभग निष्क्रिय हो चुकी हैं, तब गाजा के लोगों के हितों की रक्षा की लड़ाई अब अन्य देशों के जिम्मे आ गई है। दक्षिण अफ्रीका साहसिक कदम उठाते हुए इजरायल को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले गया और अब आयरलैंड भी इसी प्रयास में शामिल हो गया है। फ्रांस ने फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने का फैसला किया है और ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों ने गाजा में आक्रामकता को बढ़ावा देने वाले इजरायली नेताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। खुद इजरायल के भीतर भी विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। उसके एक पूर्व पीएम ने गाजा में इजरायली युद्ध अपराधों की वास्तविकता को मान्य है। इस मानवीय संकट के प्रति दुनिया भर में उभर रही वैश्विक चेतना के बीच यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है कि भारत इस मानवता के अपमान का मूकदर्शक बना हुआ है।

भारत वैश्विक न्याय का प्रतीक रहा है। उसने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैश्विक आंदोलनों को प्रेरित किया, शीत युद्ध के दौर में सामान्यवादी प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाई और रंगभेद-ग्रस्त दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय संगठनों का नेतृत्व किया। जब निर्दोष इसायों का निर्मम संहार हो रहा है, भारत का अपने मूल्यों से विमुख हो जाना राष्ट्रीय विवेक पर कलंक, हमारे ऐतिहासिक योगदान की उपेक्षा और हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति विश्वासघात भी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह 'अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून तथा संधि-करारों के प्रति सम्मान' के लिए प्रभावी कदम उठाए, पर इजरायल द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकारों और न्याय की चुनियादी अवधारणाओं की अवहेलना और उसके समक्ष हमारी वर्तमान सरकार की नैतिक कायरता हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति कार्य्यों की उपेक्षा के समान है।

भारत सदैव दो-राज्य समाधान और इजरायल तथा फलस्तीन के बीच न्यायसंगत शांति का समर्थक रहा है। 1974 में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत पहला गैर-अरब देश बना, जिसने फलस्तीन मुक्ति संगठन-पीएलओ को फलस्तीनी जनता के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। 1988 में भारत उन शुरुआती देशों में था, जिन्होंने फलस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी। इजरायल द्वारा गाजा के लोगों पर लगातार जुल्मों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की शर्मनाक चुप्पी बेहद निराशजनक है। यह नैतिक कायरता की पराकाष्ठा है। समय आ गया है कि वे स्पष्ट और साहसिक शब्दों में उस विरासत की ओर से जोरदार आवाज उठाएं, जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता आया है। आज समूची मानवता के सामूहिक विवेक की झकझोरने वाले इस मुद्दे पर ग्लोबल साउथ फिर से भारत के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है।

(लेखिका कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

# फजीहत कराता विपक्ष

विपक्षी नेता किस तरह अपने ही आचरण से अपनी फजीहत कराने में लगे हुए हैं, इसका ताजा और शर्मनाक उदाहरण है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम का यह बयान कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों के पाकिस्तान से आने का प्रमाण दिया जाना चाहिए। चिदंबरम केंद्र में गृहमंत्री ही नहीं रह चुके हैं, बल्कि वे सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। आखिर वे इतना बेतुका बयान कैसे दे सकते हैं? पहलगाम में आतंकी हमले और आपरेशन सिंदूर के संदर्भ में उनकी ओर से पूछे गए सवालों पर जो हंगामा मचा, उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। उनकी इस सफाई का कोई मतलब नहीं कि उनके बयान का गलत मतलब निकाल लिया गया। अच्छा तो कि वे अपने ही कथन को खुद सुन लें। वे पहले भी बेतुके बयान देकर विवादों में आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि बिना बिचारे ज्यादा बोल जाना उनकी आदत है। जो भी हो, चिदंबरम विपक्ष के एकमात्र ऐसे नेता नहीं जो पहलगाम, आपरेशन सिंदूर अथवा अन्य विषयों पर पाकिस्तान को रास आने वाले बयान दे चुके हैं। यह काम राहुल गांधी समेत अन्य अनेक नेता करने में लगे हुए हैं। किसी के लिए भी यह समझना कठिन है कि कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के नेता अपने बेतुके बयानों से यह बताने की कोशिश में क्यों लगे हैं कि पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले में पाकिस्तान का कहीं कोई हाथ नहीं। कम से कम कांग्रेस के नेताओं को तो पाकिस्तान की पक्षधरता करने वाले बयान देने में शर्म आनी चाहिए। आखिर वे पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर किसे खुश करना चाहते हैं? कौन हैं वे लोग जो पाकिस्तान की तारीफों करने वाले उनके बयानों से प्रसन्न होकर उन्हें वोट देना पसंद करेंगे?

कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल यह साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान प्रेरित-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ उतनी सख्त नहीं, जितना उसे होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती की कोई सीमा नहीं हो सकती, लेकिन सब जानते हैं कि मोदी सरकार के आदेश पर ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकियों के अड्डे पर बम बरसाए थे। आपरेशन सिंदूर जैसी साहसिक कार्रवाई को चर्चा तो अब भी हो रही है और संसद में भी हो रही है। विपक्ष को संसद में भी फजीहत का ही सामना करना पड़े तो हैरानी नहीं। आपरेशन सिंदूर पर संसद में विपक्ष की ओर से जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वे उसकी अक्षमण्यता को ही बयान करते हैं। हमारे संविधान और राष्ट्र निर्माताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की राजनीति इतनी अधिक सतही होगी। दुर्भाग्य से आज का यथार्थ यही है कि भारतीय राजनीति स्तरहीन होती चली जा रही है। यह संसद में भी देखने को मिल रहा है।

# सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती

पंजाब में जिस प्रकार से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, वह सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बढ़ाने जैसी है। खासकर प्रदेश के पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के बीच जिस प्रकार का गठजोड़ विकसित हुआ है, वह परेशानी बढ़ाने वाला है। आइएसआइ लगातार घातक हथियार भेज रही है। शनिवार देर रात अमृतसर पुलिस के स्पेशल सेल ने आइएसआइ की तरफ से भेजे गए घातक हथियार बरामद किए। इनमें एके-47 भी शामिल है, जिसे उन्नत कर और घातक बना दिया गया है। निस्संदेह यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। यह भी पता चला है कि आइएसआइ ने यह हथियार जेल में बंद गैंगस्टर के कहने पर भेजे थे। किस कुछ समय में सोमाली से हथियारों और मादक पदार्थों की खेप भेजने का क्रम तेज हुआ है और शायद ही कोई दिन ऐसा बीत रहा है, जब सोमवर्ती जिलों से हथियारों अथवा मादक पदार्थों की बरामदगी न होती हो। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशंसा करनी चाहिए कि वह पर्याप्त मुस्तैदी दिखा रही हैं, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सतर्कता और बढ़ानी होगी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित करना होगा। केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करते हुए सुरक्षा तंत्र को और सशक्त बनाना होगा, तभी नापाक षड्यंत्र को विफल किया जा सकता है।

# आवारा कुत्तों के आतंक से बेबस जनता

क्विज गोयल

**आवारा कुत्ते बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए खतरा बन जाएं, तो क्या जनहित को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए?**

पशु प्रेम में मानव सुरक्षा की न की जाए उपेक्षा। पाखंड

देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज की बीमारी से होने वाली मौतों की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए चिंता जताई है। भारत में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनके कारण जनजीवन और खासकर शहरी जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। यह समस्या केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक संकट भी बनती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुत्तों की संख्या छह करोड़ के करीब है, पर अनुमान है कि यह संख्या 12 करोड़ से भी अधिक है। अकेले दिल्ली में ही आठ लाख से अधिक कुत्ते हैं और हर रोज कुत्तों द्वारा काटे जाने के करीब 2,000 मामले आते हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ जैसे महानगरों में लावारिस कुत्ते सड़कों पर घूमते देखे जा सकते हैं। छोटे शहरों और कस्बों में स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि वहां इनकी देखभाल या नियंत्रण के कोई ठोस उपाय नहीं हैं। यह विडंबना ही है कि मानव द्वारा बसाए गए शहरों में अब आवारा कुत्ते के आतंक के चलते बच्चे खेलने, बुजुर्ग अकेले टहलने, लोग पैदल चलने और दोपहिया वाहन चलाने से डरने लगे हैं। अचानक हमला कर देने वाले कुत्ते जानलेवा साबित हो रहे हैं। रात के समय तो इनका आतंक और बढ़ जाता है।

सबसे भयावह समस्या है आवारा कुत्तों का काटना और उससे होने वाली बीमारी रेबीज। भारत में हर साल 15-20 लाख लोगों को कुत्ते काटते हैं और लगभग 20,000 मौतें रेबीज के कारण होती हैं। यह संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। कई बार समय पर रेबीज का टीका न मिलने पर पीड़ित की गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में तो स्थिति और भी खराब है। देश में पशु अधिकारों की बात करने वाले कई संगठन हैं, जो कुत्तों के संरक्षण के पक्ष में हैं। वे कहते हैं कि ये जीव निर्दोष हैं, उन्हें मारना या हटाना अमानवीय होगा। उनकी यह भावना सही है, पर जब यही कुत्ते बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए खतरा बन जाएं, तो क्या जनहित को प्राथमिकता नहीं मिले? एक और पशु प्रेम है, तो दूसरी ओर इंसानी सुरक्षा।

यह संघर्ष अब सड़कों और अदालतों तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक मामले में टिप्पणी की कि जिनको कुत्तों से प्रेम है, वे उन्हें अपने घर ले जाकर खाना खिलाएं, सड़कों पर नहीं। तमाम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) मांग कर रहे हैं कि सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेज जाए। शहरों में 'नो फ्राग आन स्ट्रीट पालिसी' लागू की जाए। हालांकि आवारा कुत्तों की नसबंदी कर उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए नगर निगमों के पास पर्याप्त बर्थ कंट्रोल (एबीसी) योजना है, लेकिन वह कागजों में सिमट कर रह गई है। कुत्तों की नसबंदी एवं उनका वैक्सीनेशन ठीक से हो नहीं रहा, क्योंकि यह काम मुख्य रूप से एनजीओ पर छोड़ दिया गया है, जिनमें काफी भ्रष्टाचार है। एबीसी रूल्स, 2023 में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि उसके नियम सोसायटियों पर अत्यधिक बोझ डालते हैं। इन नियमों में लोगों को कुत्तों को सोसायटी परिसर में ही खिलाने और उनके लिए जगह तय करने को कहा गया है। इससे अक्सर विवाद होते हैं।

आखिर नसबंदी के बाद भी कुत्तों को मोहल्लों, सोसायटियों में ही क्यों छोड़ दिया जाता है। जो कुत्ते आक्रामक या काटने वाले हों, उन्हें तो वहां से हटाया जाना चाहिए। आवासीय परिसरों में आवारा कुत्तों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लोग मदद के लिए सरकारी विभागों को फोन करते हैं, शिकायतें दर्ज होती हैं, लेकिन कार्रवाई न के बराबर होती है। कभी-कभी परेशान लोग कठघरे कुत्तों को मार देते हैं, तो पशु प्रेमी व्यक्ति या संगठन उन पर केस कर देते हैं। कुत्ता पालतू हो या आवारा, उसे आदमी से अधिक अहमियत नहीं मिलनी चाहिए।

आवारा कुत्तों का हल केंद्र एवं राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों के साथ मिलकर खोजना होगा। इसके लिए नसबंदी अभियान तेज, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाना चाहिए। पिछले 15 वर्षों से कुत्तों की गिनती नहीं हुई है। उनकी गिनती के साथ जीपीएस ट्रैकिंग जैसे उपाय लागू करने चाहिए। सभी शहरों में डाग शेल्टर बनने चाहिए। पशु प्रेमियों को कुत्तों को गोद लेने को कहा जाए। आज यदि हम कैब, फूड डिलीवरी और पेमेंट के लिए एप बना सकते हैं, तो आवारा कुत्तों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग के लिए क्यों नहीं? कुत्ते हमारी सभ्यता का हिस्सा रहे हैं। वे क्यादार साथी हो सकते हैं, पर उन्हें उनके कारण लोगों की जान खतरे में आ जाए, तो सह-अस्तित्व की परिभाषा बदलनी चाहिए। हमें संवेदनशीलता और व्यावहारिकता के संतुलन से इस समस्या को हल करना होगा। यह इसलिए भी जरूरी है, ताकि लोग कुत्तों को नफरत की निगाह से न देखें। केरल सरकार ने तो आवारा कुत्तों को यूथेनेशिया (जीवन समाप्त करने के वाला इंजेक्शन) देने की बात कही है। हमारी गलियां सुरक्षित बनें, बच्चे खुलकर खेलें और लोग डर के साये में न जिएं। कुत्तों के लिए भी जगह हो, लेकिन निर्दोष और सुरक्षित दायरे में।

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### विस्मृति का वरदान

स्मृति और विस्मृति एक-दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। स्मृति में व्यक्ति वह सब याद रखता है, जो उसके साथ घटा होता है। विस्मृति में व्यक्ति कुछ समय बीत जाने पर अपने अनुकूल और प्रतिकूल घटित हुई घटनाओं को भूल जाता है। हमारे शास्त्रों ने मनुष्य के जीवन पर विचार करते हुए एक स्वर में यही कहा है कि जन्म, जरा तथा मृत्यु तीन पैरों साथ हैं, जो परम दुखद हैं और सभी के साथ घटित होती हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए परमात्मा के स्मरण की आवश्यकता पर जोर दिया।

जगत की अनित्यता प्रत्यक्ष रूप में सभी को दिखाई देती है। इसी का निरंतरात्मक स्वरूप जानने के लिए कुरुक्षेत्र के रण में जब अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से अपनी जिज्ञासा प्रकट की तो श्रीकृष्ण ने यही कहा कि जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, उसका मरण निश्चित है, यद्यपि उसका पुनर्जन्म भी होता है। भगवान बुद्ध ने जब अपने शिष्यों के सिद्धांत को स्थापित किया तो कहा कि जन्म, जरा और मृत्यु ही इस संसार का सत्य है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति जो भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, वह उसे नहीं मिलता। इसी तरह से जो वह नहीं चाहता है, वह उसे अवश्य मिलता है। यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के कथन को ध्यान में रखें तो उन्होंने इस जगत की संपूर्ण प्रक्रिया को दुखात्मक बताते हुए कहा कि जन्म लेते समय और मृत्यु पाते समय प्राणी को जो दुख होता है, वह दुख अवर्णनीय है। यह कह सकते हैं कि जीव का निरंतर नौ महीने तक गर्भ में रहना और प्राणों का शरीर त्यागना ऐसे असह्य दुख हैं, जिनका कथन किन्हीं भी शब्दों के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। यह भगवान की परम कृपा है कि उन्होंने इन दुखों के साथ जीवन के छोटे-मोटे दुखों का भी विस्मरण कर देने की शक्ति हमें दी है। इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं।

डा. गदाधर त्रिपाठी

# समृद्ध भारत की राह

रेजना मिश्रा

भारत का आत्मा उसके गांवों में बसता है, और इस आत्मा की सामूहिक शक्ति का नाम है 'सहकारिता'। इसका सरल सा अर्थ है- 'मिल-जुलकर अपने विकास के लिए काम करना'। इसी विचार ने गुजरात में अमूल जैसी दूध की क्रांति को जन्म दिया, लिज्जत पापड़ के माध्यम से लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और इफको के जरिए करोड़ों किसानों तक खाद पहुंचाई। दशकों से यह सहकारी आंदोलन देश की अर्थव्यवस्था की एक मूक रीढ़ रहा है। हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 का अनावरण किया है। इस नीति का सबसे बड़ा जोर व्यवस्था को जमीनी स्तर से, यानी गांव से मजबूत करने पर है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि सहकारी समितियां केवल लीकतांत्रिक ही न हों, बल्कि पेशेवर तरीके से चलें।

नीति का एक और क्रांतिकारी पहलू सहकारिता के दायरे का विस्तार करना है। अब सहकारिता सिर्फ खेती-किसानी, दूध या चीनी मिलों तक सीमित नहीं रहेगी। यह नीति पर्यटन, स्वास्थ्य, बीमा, भंडारण, टैक्सी सेवा और यहां तक कि हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों के लिए भी दरवाजे खोलती है। यह नीति ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देती है, जिससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे। यह सहकारिता को 21वीं सदी के भारत की जरूरतों के साथ जोड़ने का एक ईमानदार प्रयास है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए पूंजी यानी धन सबसे जरूरी है। अब तक सहकारी समितियों के लिए पूंजी जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। यह नीति उन्हें बाजार से भी धन जुटाने के लिए सक्षम बनाएगी। इससे उनकी वित्तीय निर्भरता कम होगी और वे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाथ में ले सकेंगी।

**सरकार यह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे**

एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस भी बनाया जा रहा है, जो एक ही जगह पर देश की सभी सहकारी समितियों की जानकारी रखेगा। इससे बेहतर योजना बनाने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंच रहा है। यह नीति उस छोटे किसान के लिए है, जो अपनी फसल का सही दाम चाहता है। यह उस महिला के लिए है, जो घर पर रहकर भी सम्मान के साथ आजीविका कमाना चाहती है। यह उस युवा के लिए है, जो अपने गांव में ही रहकर एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखता है, लेकिन सिर्फ नीति बना देना ही काफी नहीं होता। इसकी असली सफलता इसके सही और ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इस नीति का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ऐसा होगा तभी यह नीति भारत को सामूहिक प्रयास की शक्ति से एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने की राह पर मीलों आगे ले जाएगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## घटना नहीं, चेतावनी बनें हादसे

'भारत और भगदड़' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय सामयिक और संवेदनशील विषय को सामने लाता है, लेकिन इसकी विश्लेषणात्मक परिधि सीमित रह गई है। इसमें केवल प्रशासनिक लापरवाही को लक्ष्य बनाकर बात की गई है, जबकि समस्या कहीं अधिक गहरी और बहुआयामी है। ऐसे आयोजनों में बार-बार घटने वाली भगदड़ की घटनाएं तात्कालिक विफलता से अधिक सामाजिक अनुशासन के क्षरण और जन-जागरूकता के अभाव की परिणति हैं। संपादकीय में यह चर्चा नहीं की गई कि ऐसी भीड़ मानसिकता को किस प्रकार तकनीक और शिक्षा के माध्यम से रोका जा सकता है। भीड़ नियंत्रण का प्रश्न केवल सुरक्षा बलों या अवरोधकों का नहीं, बल्कि नागरिक चेतना, डिजिटल सतर्कता और सटीक सूचना प्रबंधन का भी है। जब देश की भीड़ आंकड़ा अनियंत्रित हो और जिसरी का रूप ले, तब केवल परंपरागत तरीकों से नहीं, बल्कि नवाचार आधारित दृष्टिकोण से सोचना आवश्यक हो जाता है। भीड़ यदि जनकल्याण के लिए एकत्रित हो तो उसे अनुशासित ऊर्जा में बदलने के लिए तकनीक को लोक व्यवहार से जोड़ना ही आज की सबसे रचनात्मक नीति बन सकती है। संपादकीय में आधुनिक समाधान जैसे स्मार्ट क्राउड एनालिटिक्स, लाइव ट्राफ टैकिंग, आपातकालीन चेतावनी तंत्र और आयोजन-पूर्व भाक द्विज जैसी रणनीतियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इंटरनेट मीडिया पर फैलती अफवाह, प्रशिक्षित क्राउडवेयर फोर्स की भूमिका और मीडिया की जवाबदेही जैसे आयामों की भी उपेक्षा की गई है। जब घटनाएं दोहराई जाने लगें, तब विपत्तों का

## प्रतिक्रिया

दायित्व केवल आलोचना नहीं, समाधान सुझाना होता है। प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति से बदलाव संभव नहीं। जरूरी है कि अब चिंतन 'क्या हुआ' से आगे बढ़कर 'क्या होना चाहिए' पर केंद्रित हो।

awanishg30@gmail.com

## देशहित में हो समझौते

ब्रिटेन के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से पहले वर्ष में भारत को लगभग 4,060 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। इसमें विभिन्न वस्तुओं पर शुल्क को या तो कम किया गया है या समाप्त कर दिया गया है। वैश्विक स्तर की आर्थिक शोध संस्थान 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव' ने ब्रिटेन से संभावित आयात आंकड़ों के आधार पर यह आकलन प्रस्तुत किया है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त व्यापार समझौते से देश को लाभ भी हो, आयात-निर्यात का संतुलन न बिगड़े और कुटनीतिक मामलों में ब्रिटेन भारत का दिल खोलकर समर्थन करे। यह समझौता केवल व्यापारिक विषयों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वैश्विक कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर भी देश के हित में होना चाहिए।

सुगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

## चुनाव आयोग पर भरोसा करे विपक्ष

बिहार में चुनाव आयोग का मतदाता सूची सत्यापन एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण किया है। इसके परिणामस्वरूप 60 लाख से अधिक लोग ऐसे पाए गए हैं, जो राज्य में वोट डालने के योग्य नहीं हैं। यह कार्य चुनाव आयोग का प्रमुख दायित्व है, जिसे उसने संकल्पपूर्वक निभाया है। यदि मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं किया जाता, तो ये फर्जी मतदाता बिहार के चुनावों को प्रभावित कर सकते थे। कांग्रेस और उसके प्रभावी नेताओं को आयोग के ऐसे कदमों का समर्थन करना चाहिए, जिससे चुनाव की निष्पक्षता साबित हो सके। बिहार के संदर्भ में मतदाता सूची के पुनरीक्षण ने निष्पक्षता को बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार चुनाव आयोग का अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण का निर्णय सही है। यह सच है कि किसी भी चुनाव में हार-जीत चलती रहती है। कांग्रेस और विपक्ष को सकारात्मक राजनीति अपनाकर खुद को स्थापित करना चाहिए, न कि हार का ठीकरा ईवीएम या चुनाव आयोग पर डालना चाहिए।

डा. प्रदीपकुमार सोंधी, झाबुआ

इस रूम में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रसिद्धित व्यक्त करने के लिए पाठकगण लाइव अभीहित हैं। आप हमसे पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संपादक- रा. पूर्णचंद गुप्त, पूर्व संपादक संकटक- रा. रोहित मेहरा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर- ऑन लेकर गुप्त, प्रकाशन प्रकाशकाशित, के लिए, रोहित प्रिंटिंग प्रेस द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, जंतरमंतर से प्रकाशित और उसी के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)- विष्णु प्रकाशचिपाठी*
दूरभाष : जंतरमंतर कार्यालय : 011-43566300, नोएडा कार्यालय : 0120-6615800, E-mail: delhi@mda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समाचार सामग्री के पठन एवं संकलन हेतु पी. आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उपलब्ध। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। हार्ड/ऐन शुल्क ₹ 2 अतिरिक्त।

********

**815** किलोमीटर लंबी है थाइलैंड और कंबोडिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा। यहां बसी पर स्थित एक मंदिर को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में कंबोडिया को सौंप दिया था। दोनों देशों के बीच यही भूमि घटी पर विवाद कायम है।

विवेक ओझा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

थाइलैंड और कंबोडिया के बीच लगभग आठ सौ किमी लंबी सीमा दशकों से विवादित रही है। इस ताजा टकराव की जड़ें सौ साल पुरानी हैं, जब फ्रांसीसी उपनिवेश काल के दौरान दोनों देशों की सीमाएं तय की गई थीं, तब से अब तक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और खासकर एक खमेर-हिंदू मंदिर को लेकर कई बार खूनी टकराव हो चुके हैं। हालिया तनाव मई में और बढ़ गया, जब एक कंबोडियाई सैनिक एक झड़प में मारा गया। उसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान थाइलैंड ने कंबोडिया के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1946 में उसे फ्रांसीसी शासन को वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों देशों के बीच 2008 में 900 साल पुराने एक मंदिर से सटे जमीन के टुकड़े को लेकर सैन्य झड़पें हुईं। वर्ष 2012 में प्रेह विहार मंदिर के आसपास हुई झड़पों में दर्जनों सैनिक मारे गए थे। इस मंदिर को 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया को सौंप दिया था। दोनों देशों के बीच 4.6 किमी लंबी भूमि पट्टी पर विवाद है। थाइलैंड इसपर अपना दावा करता है।

ताजा संकट की शुरुआत 28 मई को हुई, जब थाई सेना के साथ सीमा पर हुई गोलीबारी में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। दोनों पक्षों ने आधारहीन में गोलीबारी की बात कही। इस बीच पूर्व कंबोडियाई नेता हुन सेन के साथ थाई प्रधानमंत्री शिनावात्रा की लीक फोन कॉल ने थाईलैंड में राजनीतिक भूचाल ला दिया। शिनावात्रा पर थाई सेना की कमजोर करने का आरोप लगते हुए उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया था।

**भारतीय हित :** दक्षिणपूर्व एशिया में क्षेत्रीय रणीति का बन रहना भारत के हितों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सबंधित है कि थाईलैंड और कंबोडिया आसियान के सदस्य के रूप में भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आसियान क्षेत्र में अभी तक म्यांमार राजनीतिक विकर्टों और नृजातीय संघर्ष के लिए जाना जाता रहा है जिससे भारत पर भी असर पड़ा। एक बार किसी भी क्षेत्र में विकट शुरू होने के बाद विकट या युद्ध की स्थिति द्विपक्षीय नहीं रह पाती और कई अन्य प्लेयर्स को खेल खेलने का मौका मिल जाता है। भारत ने पिछले कुछ ही समय से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को ब्रह्मोस मिसाइल सहित कई अन्य रक्षा उपकरणों का निर्यात करना शुरू किया है, उससे मिलने वाले लाभ पर किसी न किसी रूप में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत- म्यांमार- थाईलैंड ट्राईलेटरल हाइवे प्रोजेक्ट में अब कंबोडिया भी शामिल हो चुका है और भारत के लिए यह एक जरूरी रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ऐसे में इसके दो सदस्यों के बीच का संघर्ष सकारात्मक कार्यवहियों में भी खलल डाल सकता है। भारत थाईलैंड और कंबोडिया के विकट में जिस तरह स्टैंड लेगा, उससर यह निर्धर करेगा कि हमारे आर्थिक, सममरिक एवं रक्षा संबंधों पर कोई गलत प्रभाव न पड़े।

बिम्सटेक के संस्थापक सदस्यों और बंगाल की खाड़ी को दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और थाईलैंड की अहमी भूमिका रही है। ईंदो पेसिफिक से जुड़ी सुरक्ष, दक्षिण चीन सगर विकाद में दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों को चीन के खिलाफ एकजुटता, हिंद महासागर से जुड़ी चुनौतियों का समना करने में 'आसियान सेंट्रलिटी' की मजबूत बनए रखने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिय में किसी भी प्रकार के विकट का समाधान जरूरी है। दक्षिणपूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया में दुनिया की बड़ी ताकतें कैसे रुचि लेती हैं इसे आसियान, ईस्ट एशिया समिट, एपेक की बैठकों में देखा जा सकता है।

भारत के इस क्षेत्र के साथ आर्थिक हित, सममरिक हित (इंडो पेसिफिक स्ट्रेटजी, एक्ट ईस्ट पालिसी, नेकलेस आफ डायमंड पालिसी) जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म के सतर पर भारत थाईलैंड और कंबोडिया दोनों से कनेक्टेड है। मेकांग गंगा कोआपरेशन पहल के जरिए भी भारत इन दोनों देशों से क्षेत्रीय सहयोग के लिए जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारत थाईलैंड और कंबोडिया के विकट का तत्काल शांतिपूर्ण समाधान चाहेगा।

अगर युद्ध में रूस के हथियारों का उपयोग कंबोडिया करेगा तो इस मामले में अमेरिका भी हस्तक्षेप करेगा ही और चीन अपने आर्थिक एवं सममरिक मंसूबों के लिए इन दोनों देशों को ही अलग-अलग सतर पर डील करने से भी नहीं चूकेगा। चीन और अमेरिका दोनों के इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी हित कायम हैं। कंबोडिया ने 'गल्फ आफ थाईलैंड' के पास चीनी नौसेना को नौसैनिक अड्डे पर 'नेवल एक्सेस' दिया है जो दक्षिण चीन सागर के निकट स्थित है, जहां चीन के अवैध समुद्री दावे विकट का विषय बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने नेकलेस आफ डायमंड पालिसी के तहत सिंगापुर के चांगी और इंडोनेशिय के सबांग नौसैनिक अड्डे तक पहुंच की लेकर समझौता किया है। भारत की इस पालिसी में वियतनाम भी शामिल है।

इस विकट के समाधान के लिए महत्वकियों की मध्यस्थता आवश्यक है। किसी धार्मिक स्थल को लेकर विकट उभरने का हल कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा इजरायल और अरब देश अल अक्सा मस्जिद के संदर्भ में देख चुके हैं। इसलिए इस समस्य के समाधान के लिए सभी संबंधित पक्षों को व्यावहारिक रूप से सोचना और आगे बढ़ना होगा। एक ऐसे समय में जब महामारी, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्लीवल वार्मिंग और जलवयु परिवर्तन का मार पहले से ही दुनिया के सतत विकास को तुच्छाघातिक कर रही है, ऐसे में संकीर्ण लाभों के लिए राजनीतिक सैन्य विकट उभरना विजन के अभाव का परिचायक है।

सैन्य संघर्ष से प्रभावित कंबोडिया में एक रहत शिविर में शरण लिए लोगों के बीच किया जा रहा भोजन सामग्री का वितरण। पाइल

थाइलैंड-कंबोडिया सैन्य संघर्ष

# दक्षिणपूर्व एशिया की क्षेत्रीय शांति में बाधा

**थाइलैंड और कंबोडिया के बीच हालिया सैन्य संघर्ष इस बात का साक्ष्य है कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में राष्ट्रों के बीच विवाद आसानी से उभर रहे हैं। साथ ही, राष्ट्रों में सहिष्णुता और धैर्य की जगह निजी स्वार्थ एवं आवेश बढ़ता जा रहा है। थाइलैंड और कंबोडिया जैसे पड़ोसी देशों ने एक दूसरे पर हथियार चलाकर एक गंभीर क्षेत्रीय अशांति की स्थिति को पैदा किया। इसमें 30 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और दो लाख से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि इस बीच अच्छी बात यह है कि ये देश अब शांति कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं**

## हिंद-प्रशांत रणनीति नए सिरे से आगे बढ़ाए भारत

ल. एम. एल. मीणा
विभागाध्यक्ष, भूगोल, हरियाणा केंद्रीय वि, महेंद्रगढ़

दक्षिणपूर्व एशिया में कंबोडिया-थाइलैंड सीमा विवाद ने एक बार फिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति की परिधारित करने वाली नाजुक अंतर्धाराओं को उजागर कर दिया है। हालांकि यह टकराव जमीन, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय दावेदारी को लेकर स्थानीय संघर्ष की तरह लग सकता है, लेकिन ऐसे संघर्षों के झटके अक्सर ताकतिक धुरोल से कहीं आगे तक गूंजते हैं। दक्षिणपूर्व एशिय और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र से गहरे जुड़ाव वाले एक सध्यतागत राष्ट्र भारत के लिए कंबोडिया-थाइलैंड गतिरोध एक चेतावनी भी है। वस्तुतः कंबोडिया-थाइलैंड तनाव के मूल में ऐतिहासिक शिकायतें, राष्ट्रीय पहचान की राजनीति और क्षेत्र में कमजोर होते बहुपक्षवाद के कारण उत्पन्न रणनीतिक शून्यता का मिश्रण निहित है। औपनिवेशिक काल की सीमाओं में निहित मंत्रि से जुड़ा विवाद केवल एक मानचित्र संबंधी विसंगति नहीं है। यह दर्शाता है कि कैसे विरासत के प्रतीक अक्सर संप्रभुता के युद्धक्षेत्र बन जाते हैं।

कंबोडिया-थाईलैंड विवाद का मूल औपनिवेशिक मानचित्रकला और सांस्कृतिक विरासत पर प्रतिस्पर्धा में निहित है। वस्तुतः वर्ष 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कंबोडिया को प्रदान किया गया प्रेह विहिर मंदिर, ऐतिहासिक रूप से थाइलैंड की और एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। निकटवर्ती क्षेत्र को लेकर असफटता दावों की विकट का विषय रही है, जिस कारण बार-बार सैन्य झड़पें होती रही हैं। भारत को इस पर्यवेक्षण के रूप में देखना चाहिए कि कैसे छोटे-छोटे संघर्ष महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा के केंद्र बन सकते हैं, खासकर जब दक्षिणपूर्व एशियाई देशों पर चीन का साथ मंडरा रहा हो। कंबोडिया में बुनियादी ढांचे के लिए चीनी निवेश ने उसे बेहिसाब कर्ज दिला दी है। इसके और, थाईलैंड ने अमेरिकी सुरक्ष क्षेत्र और चीन की आर्थिक उदारता के बीच रणनीतिक हेजिंग के बढ़ते संकेत दिखाए हैं।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति और उसकी हिंद-प्रशांत महासागर पहल इसी संदर्भ में बनाई गई थी। यह एक ऐसे दृष्टिकोण का प्रतीक है जहां भारत न केवल एक संयोजक है, बल्कि इस क्षेत्र में एक आज्ञायी भागीदार भी है। इस संदर्भ में कंबोडिया-थाईलैंड विवाद भारत की विश्वसनीयता के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। यह भारत को अपनी नैतिक एवं कूटनीतिक क्षमता को और मजबूत करने का निर्मंत्रण है। कूटनीति, सांस्कृतिक संकट मंथों और यहां तक कि आशियान-मेतृत्व वाले मंचों जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से भारत गैर-आधिपत्यकारी स्थिरता की आवाज बनकर उभर सकता है। कंबोडिया और थाईलैंड भारतीय सांस्कृतिक जड़ों और हमारी सौम्य शक्ति एवं ऐतिहासिक संबंधों से बंधे हुए हैं। लिहाजा, ऐसे समय में जब तमाम देशों के बीच भू-सांस्कृतिक कूटनीति बढ़ रही है, भारत अपने प्राचीन संबंधों, बौद्ध विरासत, समुद्री व्यापार विरासत और प्रवासी नेटवर्क के माध्यम का लाभ उठाकर संघर्ष के बजाय संवाद को बढ़ावा देने वाले आख्यानों को सुरक्षित करने में सक्षम है। आश्रिकार पेस क्षेत्र में जहां मंदिर युद्धक्षेत्रों में बदल जाते हैं, भारत की समन्वयकार और सभ्यतागत परिपक्वता की आवाज पहले से कहीं अधिक मायने रखती है।

इस घटना से भारतीय रणनीतिकारों को यह याद दिलाना चाहिए कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र केवल एक समुद्री क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह बहुसंस्कृतिक और बहुआयामी है। लिहाजा भारत की रणनीतिक गणना नौसैनिक तैनाती और रक्ष संबंधों से आगे बढ़ने चाहिए। कंबोडिया-थाईलैंड विवाद भारत को हिंद-प्रशांत रणनीति को फिर से सशाजुधारिपूर्ण जुड़ाव, सभ्यातगत एकजुटता और निवारक कूटनीति के रूप में परिभाषित करने का आह्वान है।

## खरी-खरी

### अग्नि परीक्षा

दूल सल्ला

दुल्हन के प्रवेश के साथ ही दूल्हे की शर्त सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दूल्हे की मांग थी कि दुल्हन को पहले अग्नि परीक्ष देनी होगी। सारा मोहल्ला दूल्हे की धैष्कण से हतप्रभ था। मुझे जानकारी हुई तो हैरानी से अपने पत्नी का मुंह ताकता रह गया। पत्नी बोली- 'जाओ उसे समझाओ कि यह जिद ठीक नहीं है। बिना बात वह अग्नि परीक्षा क्यों कर देगी? न कोई रुवज उसे अपने लंका में ले गया, न ही उसने कोई गलत कार्य किया है।'

मैंने कहा- 'मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि दूल्हे की ओर से यह मांग उठी क्यों है? सात फेरों के समय उसने जो शपथ लेकर उसकी अर्धांगिनी होना स्वीकारा है, क्या वह पर्याप्त नहीं है।'

'दरअसल दूल्हे का मानना है कि यदि दुल्हन सती-सवित्री है, तो उसे अग्नि परीक्ष में कुछ नहीं होगा।'

'अरे छोड़िए, फालतू बात। आपको भी देनी पड़ जाती मेरे सामने तो अग्नि परीक्षा।'

मैंने कहा- 'यह तो पारमपरिक विश्वास की बात है- वरन यह शर्त तो हम भी लगा सकते थे।'

मैं चूप रहा। दूल्हे के घर पहुंचा तो वह बैठक में परशुरामजी की तरह क्रोध में नाक फुलाए इधर-से-उधर टहल रहा था। मैंने छूटते ही कहा- 'इस जमाने में तुम्हारे यह मांग अनुचित है। यह कलियुग है। दुल्हन का अग्नि में कूदने का मतलब वह अपनी जान से हाथ धो देगी।'

दूल्हे ने कहा, 'मेरा आशय कोई समझ नहीं रहा और आत का बतंगड़ बन रहा है। मैं कहता हूं कि उसे अग्नि परीक्ष देनी होगी। वह इससे इन्कार क्यों करती है?'

मैंने कहा- 'वह इसलिए मन कर रही है, क्योंकि यह गलत परंपरा है। अभी यदि तुम्हारे कहने से उसने परीक्ष दे दी तो उसका अनुसरणी होना निश्चित है। इसलिए ऐसी कोई जिद मत करो जिससे कानून और व्यवस्था प्रभावित हो।'

'इसमें कानून और व्यवस्था कहां से आ गई,' दूल्हा बोला।

मैंने समझाया, 'जहां तक कूदने की बात है, वह तैयार है, परंतु युग की मान्यताओं को आधात लगता है। सत्य तो यह है कि दहेज के कारण उसे अग्नि परीक्ष तो देनी ही है, परंतु अभी चार दिनों के लिए तो उसे तुम हृदय से स्वीकार कर स्नेह दो।'

## पोस्ट

कुछ तो भी जीत से कम नहीं होते। शून्य पर दो विकेट गंवाने, 300 से अधिक रनों से पिछड़ने और करीब दो दिनों तक खल्लीटी की चुनौती को देखते हुए कुछ ही लोगों को यह उम्मीद रही होगी कि हम मैनचेस्टर टेस्ट बचा सकेंगे।

विक्रम पंढ़@vikramchandra

हत्या की तस्वीरें फैसे विचलित करती है, लेकिन धर्म पूछकर गोली मारने वाले आतंकियों का हश्र सबको दिखना चाहिए। हमारी सेना दुढ़-दुढ़ कर हिसाब पूरा करती है, यह भी याद रहना चाहिए।

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

अमेरिका में आयातित तमाम वस्तुओं के मामले में ट्रंपतनाम ने चीनी वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया है। कायदे से चीन एलस उन सी यह रणनीति भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर थी, लेकिन ऐसी सभावनए साकार नहीं हो सकीं।

सयनस धूमे@dhume

कांग्रेस नेताओं के रोधने का तरीका ही समझ में नहीं आता। अब दो, थिवरम कह रहे हैं कि हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि पहलगाम के हत्यारे आतंकी पाकिस्तानी थे?

हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

## जागरण जनमत

दल का विचार

**क्या गनना देवी हादसा प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है?**

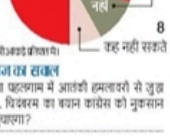


स्थानीय लोगों से बातचीत पर आधारित।

### आज का सवाल

क्या पहलगाम में आतंकी हमलावरों से जुड़ा पी. थिवरम का बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा?

परिणाम जागरण ह्वाट्सएप सर्वरण के पाठकों का है।

## जनपथ

जिनसे मिलती ना प्रकृति ना आधार-विचार,
बनते ऐसे लोग ही बीजेपी पर भार।
बीजेपी पर भार वहे ही प्रादाधनसह,
चाहे पीरी, शाह और सिन्हा की खड़ाऊं।
रहिए दस पग दूर स्वय को सदैव ऊनरी,
मिलता नहीं विचार आपका बिल्कुल जिनसे।।

- ओमप्रकाश तिवारी

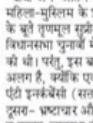

जयकृष्ण गउपेयी
राज्य भूरे ब्यूरो, बंगाल

बंगाल डायरी

# 'चौथी जंग' जीतने को ममता ने बनाया 'त्रिकोण'

महिला, मुस्लिम और भाषा। इन तीनों का 'त्रिकोण' बनकर बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी 2026 की अपनी 'चौथी जंग' जीतने की तैयारी में हैं। महिला-मुस्लिम के इसी समीकरण के बूते तृणमूल सुप्रीमो ने पिछले तीन विधानसभा चुनावों में सफलता हासिल की थी। परंतु, इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि एक तो 15 वर्षों का एंटी इनकंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर)। दूसरा- भ्रष्टाचार और तीसरा- बेरोजगारी व कानून-व्यवस्था जैसे अहम ज्वलंत मुद्दे हैं, इसीलिए ममता ने महिला-मुस्लिम के साथ अब बांग्ला भाषा को जोड़ दिया है, ताकि बंगाली भावना और अस्मिता को लेकर एक ऐसा त्रिकोण बनाया जाए, जिससे चौथी बार भी जीत की राह आसान हो जाए।

जीत में किसी तरह का संशय न रह जाए, इसके लिए पिछली बार की तरह इस बार फिर चुनाव पूर्व लोक-लुभावन नई घोषणाएं शुरू कर दी हैं। मंगलवार को ममता सरकार ने घोषणा कर दी है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल ने अपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर 'दुआरे सरकार' यानी 'दरवाजे पर सरकार' योजना शुरू की थी। वर्तमान में भी प्रशांत किशोर हाल ही में 'दीदिके बोलो' जैसी योजना 'आइपैक' तृणमूल के लिए काम कर रही है। इस बार ममता दो अगस्त से 'आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान' यानी 'हमारा मोहल्ला, हमारा समाधान' योजना शुरू करने जा रही हैं। तृणमूल सुप्रीमो ने 21 जुलाई को हुई रैली से पहले ही इसकी घोषणा की थी। इसके 24 घंटे बाद ही नई सरकारी योजना की भी घोषणा कर दी। इस योजना का मकसद सरकारी सेवाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाना है। इसी लागू करने के लिए तृणमूल के नेता-कार्यकर्ता सरकारी व्यवस्था के समानांतर गांव-गांव जाएंगे। प्रत्येक बूथ के लिए 10-10 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। अधिकारी बूथ स्तर पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

राज्य में कुल 80 हजार बूथ हैं। इस आंकड़े के साथ इस कार्यक्रम पर राज्य के खजाने से 80 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हर मोहल्ले की छोटी-बड़ी मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जैसे सड़कें बनाना, पीने के पानी के नल लगवाना, ग्रमीण इलाकों में छोटे पुलों की मरम्मत, स्कूलों के बुनियादी ढांचे का विकास। सरकार उन सभी को पूरा करने का प्रयास करेगी। तृणमूल नेताओं का कहना है कि जब एक ही पार्टी लगातार 15 वर्षों से सरकार चलाती है, तो एंटी इनकंबेंसी होना स्वाभाविक है। यह भी स्वाभाविक है कि विपक्ष इसका इस्तेमाल करना चाहेगा। ऐसे में अगर सरकार गांवों, मोहल्ले तक पहुंचती है तो स्थानीय स्तर पर आक्रोश भी शांत होगा। यह कार्यक्रम इसे दृष्टिकोण से लाया गया है। आमतौर पर लोगों का यह सेच होता है कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो उन्हें प्रशासन के पास जाना होगा। इस बार वे देखेंगे कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उन तक पहुंच रही है।

तृणमूल की 21 जुलाई की रैली में मुसलमानों और महिलाओं की उपस्थिति गैर करने लायक थी। ममता के जन समर्थन का मुख्य आधार महिला-मुस्लिम ही रहे हैं। इसे देखकर तृणमूल बेहद आश्वस्त है। ममता ने 21 जुलाई के मंच से एक और भाषा आंदोलन का आह्वान किया था। दरअसल तृणमूल के अग्रिम पंक्ति के नेता 'भीड़ को भाषा' पढ़ना चाहते थे। सनातन्दू दल उस भीड़ को पिछले लोकसभा चुनावों के आलोक में आगामी विधानसभा चुनाव के आधार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया कि भाजपा ने कई शहरी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तृणमूल को गांवों में विशेष समर्थन मिला। लोकसभा चुनाव ने साफ कर दिया था कि मुस्लिम और महिला वेट ममता के साथ हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने बांग्लाभाषी और भाषा आंदोलन शुरू किया है, उससे साफ हो गया है कि बाकी सभी मुद्दों को वह गौण करना चाहती हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की मतगणना तक भाषा आंदोलन जारी रहेगा, उससे साफ हो गया है कि उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ देश के अन्य राज्यों में कार्रवाई हो रही है, उसमें जो मुस्लिम हैं, उन्हें बांग्लाभाषी बताया एक राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि बांग्लादेश में भी बांग्ला ही बोली जाती है। इससे यहां के मुस्लिम वोटरों को एकजुट रखने में मदद मिलेगी, वहीं महिलाओं को हर माह एक हजार से 1,200 रुपये देने की 'लक्ष्मी भंडार' और 'कन्याश्री' जैसी नकदी बांटने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं भाजपा बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में है। तृणमूल इसे रोकने के लिए जबकी रणनीति बना रही है। ममता सरकार मुसलमानों और महिलाओं का समर्थन मजबूत करते हुए बंगाली अस्मिता के साथ-साथ विकास के हथियार से ध्रुवीकरण को कुंद करना चाहती है। दीघा में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बाद ममता ने 'दुर्गा आंगन' (देवी दुर्गा का मंदिर) बनाने की भी घोषणा की है। यही नहीं, 31 जुलाई की ममता ने दुर्गापूजा कमेटियों की बैठक भी बुलाई है, जिसमें वह सरकार की ओर से पूजा आयोजकों को दी जाने वाली 85-85 हजार रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की घोषणा कर सकती हैं। इन कवायदों और महिला-मुस्लिम-भाषा के 'त्रिकोण' से ममता अपनी चौथी जंग जीत पाती है या नहीं, यह आगमी वर्ष पता चलेगा।

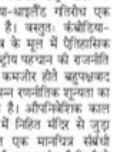

इसी वर्ष्ट्रद के दौरान ममता कर्जी। पाइल

मंथन

# दुनिया पर छाने को तैयार रोबोट

**अनेक विधाओं में रोबोट के उपयोग को संभव बनाते हुए तमाम देश इनकी संख्या को निरंतर बढ़ा रहे हैं। भारत समेत समूचे विश्व में इस मद में बड़ी रकम खर्च करने की तैयारी है**

कृपभ मिश्र
असिस्टेंट प्रोफेसर, कानपुर इंडस्टीयूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर

प्रतीकात्मक

मेडिकल सर्जरी में एआइ निर्देशित रोबोट्स तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में दावा किया है कि अगले पांच वर्षों में रोबोट सर्वजेक्ट सर्जनों से भी बेहतर हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा उपकरण कंपनी 'मेडट्रानिक' के 'ह्यूगो' रोबोट को इंटरनेट मंडिया पर दिखाया गया था। ह्यूगो रोबोट का हाल ही में यूके से अधिक सर्जरियों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। हो सकता है कि मेडिकल क्षेत्र में रोबोट्स का पूर्णकालिक उपयोग अभी दूर की कौड़ी हो, फिर भी मस्क के दावे को गलत नहीं कहा जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में दुनियाभर में रोबोट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और अनेक देश इस पर अरबों डालर का निवेश भी कर रहे हैं।

इसी प्रकार जापान का 'सोसाइटी 5.0' एक महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें रोबोट्स के जरिए सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए अगले 10 साल में 100 अरब डालर खर्च करने की योजना है। जापान के टोयोटा रोबोट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ह्यूमेनाइड रोबोट्स के सहायक प्रौद्योगिकी के लिए एक अरब डालर का निवेश किया है। यूरोप ने भी रोबोटिक्स रिसर्च पर 108 अरब डालर खर्च किया है। 'यूरोपियन रिजन यूरोप' के तहत 2021-27 के बीच रोबोटिक्स व एआइ रिसर्च के लिए 108 अरब डालर का बजट रखा गया है। वहीं रोबोटिक्स रिसर्च के लिए यूरोपीय यूनियन 80 करोड़ डालर का निवेश कर रहा है।

**उपयोग में निरंतर वृद्धि :** औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रियाओं में एआइ संचालित रोबोट्स का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 'प्रीडी प्रिंटिंग' रोबोट्स के साथ ही सर्विस क्षेत्र में भी इनकी मांग बढ़ रही है। कुल रोबोट्स में से 18 प्रतिशत सर्विस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनमें अधिकांश रोबोट्स होटलों व रेस्टोरेंट्स में खाना 'सर्व' करने व सफाई जैसे कार्यों में लगे हैं। तो वहीं बुजुर्गों की देखभाल और कृषि के क्षेत्र में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है। खासकर उन देशों में जहां खेती ज्यादा है और श्रमिक कम, वहां ये काफी उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ड्रोन और रोबोट के माध्यम से फसलों की निगरानी की जा रही है।

वहीं यदि रोबोटिक्स में भारत के योगदान की बात करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन आफ रोबोटिक्स की वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सबसे ज्यादा 8,510 नए रोबोट 'इंस्टाल' हुए जो एक साल पहले की तुलना में 59 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। भारत अब रोबोट इंस्टालेशन में दुनिया में सातवें नंबर पर आ गया है। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) योजना भी इस क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्सहित कर रही है। भारत में इस समय निजी क्षेत्र में लगभग 21 कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें टिफिकोरोबोटिक्स और सिस्टेमेटिक्स जैसे उभरते स्टार्टअप्स से लेकर बड़ी स्थापित कंपनियां शमिल हैं।

भारत के विभिन्न औद्योगिक संस्थान भी रोबोटिक्स पर काम कर रहे हैं। आइआइटी मद्रास ने 'थ्रियर' रोबोट और स्मार्ट प्रोस्थेटिक्स का विकास किया है। आइआइटी कानपुर रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर पर काम कर रहा है। टूरिज्म आइटी हैदराबाद कृषि में आटोमेशन के लिए ड्रोन और रोबोट्स का विकास कर रहा है। भारत सरकार ने 'नेशनल स्ट्रैटेजी आन रोबोटिक्स' का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य देश को 2030 तक रोबोटिक्स में लीडर बनाने के लिए प्रयास करना है।

दक्षिण कोरिय वर्ल्ड रोबोटिक्स के अनुसार, दक्षिण कोरिया 10 हजार कर्मचारियों (प्रति) पर एक हजार औद्योगिक रोबोट्स के साथ दुनिया में सबसे अधिक रोबोट घनत्व वाला देश है। वैश्विक औद्योगिक रोबोट के मामले में 45 प्रतिशत आपूर्ति जापान से हुई है। तो वहीं गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, ह्यूमेनाइड रोबोट का मार्केट वर्ष 2035 तक 38 अरब डालर का हो जाएगा, इससे इस क्षेत्र का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में रोबोट्स के बढ़ते प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सहारा
पटना • मंगलवार • 29 जुलाई • 2025
www.rashtriyasahara.com



अनमोल वचन

*अपने सकारात्मक विचारों को ईमानदारी और बिना थके हुए कार्यों में लगाए और आपको सफलता के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपितु अपरिमित सफलता आपके कदमों में होंगी*
-अज्ञात

## घोर लापरवाही

हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ में आठ श्रद्धालु मर गये तथा तीस से अधिक गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। यह मंदिर पहाड़ी पर है, जहां पहुंचने के लिए आठ सौ सीढ़ियां हैं। मृतकों में चार उप्र के व एक-एक बिहार व उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। सावन माह में मंदिर में भारी भीड़ होती है। बताया जा रहा है कि मंदिर से करीब सौ मीटर पहले ही धक्का-मक्की के चलते करीब लटक रहे तार को सहारे के लिए लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, जिससे करेंट लगने से अफरा-तफरी मच गई। हड़बड़ाहट में कुछ लोगों के गिरते ही भगदड़ मच गई। हरिद्वार की शिवालिक पहाड़ियों पर बना यह मंदिर बिल्व पर्वत पर पौड़ी से तीन किलोमीटर दूर है। महंत इसे मंदिर परिसर के भीतर नहीं हुई घटना कह कर हाथ झाड़ रहे हैं और सरकार ने मुआवजा घोषित कर रस्म अदा कर दी। इसी समय उप्र के बाराबंकी के औसानेश्वर मंदिर में मची भगदड़ में दो की मौत हो गयी। मृतक के भाई का आरोप है, वहां तार सुलगते देखा गया था। पूजास्थलों में चढ़ावा और श्रद्धालुओं को बटोरने की होड़ किसी से छिपी नहीं है। स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकारें श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने का जिम्मा सलीके से लेने में क्यों असफल हैं। महीना भर पहले ही पुरी में रथ-यात्रा के दौरान मची भगदड़ में तीन भक्तों की मौत हुई है। उससे पहले गोवा में भंदिर उत्सव में भगदड़ में छह मरे थे और इसी जनवरी में तिरुपीति में भी छह श्रद्धालु कुचल कर मारे गए थे। देश के विभिन्न धर्मस्थलों में प्रतिवर्ष होने वाले इन धार्मिक आयोजनों के बारे में सबको पहले से खबर होती है। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला मुल्क अपने बाशिंदों की जान को लेकर कितना संवेदनहीन हो रहा है। खासकर धर्म को अपना मुख्य एजेंडा बनाने वाली सत्ताधारी पार्टी का जिम्मा है कि वह भक्तों की सुरक्षा के प्रति लापरवाह रवैया बदले। किसी भी बड़े धार्मिक उत्सव/त्योहार को लेकर आयोजकों, मंदिर व्यवस्थापकों व स्थानीय प्रशासन व पुलिस को चेतावनी देनी होगी। समाज में धर्मपरायण व मान्यताओं के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वालों की संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। विशेष अवसरों पर पूजा-अर्चना करने वालों की संख्या साल-दर-साल बढ़ती ही है। प्रशासन व पुलिस को भीड़ संभालने का प्रशिक्षण दिया जाए। भगदड़ जैसी घटनाएं घोर लापरवाही की श्रेणी में आती हैं। मुआवजों के भरोसे व्यवस्था नहीं सुधारी जा सकती। इस पर केंद्र को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए।

## स्कूली इमारतों में असुरक्षा

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर स्कूलों में बच्चों से जुड़ी संरचनाओं तथा सुरक्षा तंत्र का ऑडिट करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की इमारत का हिस्सा गिरने के मद्नेनजर उठाया गया है। गौरतलब है कि 25 जुलाई को हुए इस हादसे में सात बच्चों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए थे। इसे देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली इमारतों में संरचनात्मक समग्रता, अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास और बिजली के तारों का गहन मूल्यांकन करने को कहा है। कर्मचारियों और छात्रों को आपातकालीन तैयारियों का प्रशिक्षण, जिसमें निकासी अभ्यास, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हों, सुनिश्चित करने को भी कहा है। हाल के समय में स्कूलों में कई दुखद घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई छात्र असमय काल के गाल में समा गए। जाहिर है कि यह कदम काफी देर से उठाया गया है, लेकिन निश्चित ही सराहनीय है, जिसमें नौनिहालों के जीवन को लेकर सरकार की संजीदगी का पता चलता है। राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग और पंचायती स्तर पर स्कूली इमारतों के निर्माण कराए जाते हैं। जरूरी है कि निर्माण गुणवत्तापूर्ण हों। निर्माण सामग्री घटिया न हो। इसके लिए इन विभागों में निगरानी तंत्र होता है। यदि कोई इमारत मियाद पूरी करने से पहले ही जर्जर होकर धराशायी होने के कगार पर जा पहुंची है, तो निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के साथ ही लापरवाही और सरकारी धन की बंदरबांट बड़े कारण हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि स्कूली इमारतों में निर्माण के स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। ऐसा होता है तो इस प्रकार की दर्दनाक घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार के ही कई विभाग हैं, जो अपने लिए जरूरी निर्माण कार्य अपने तई विभाग गठित करके पूरा कराते हैं। इन विभागों का प्रमुख दायित्व निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना होता है यानी अपनी नजरों के सामने निर्माण कराए जाने को तरजीह दी जाती है। यहां तो मसला होनहारों का है, जिन्हें किसी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होने दिया जा सकता। अच्छी बात है कि सरकार ने सभी स्कूली इमारतों की सुरक्षा जांच को कहा है। यह भी जरूरी है कि असुरक्षित स्थितियों पर सतत कड़ी नजर रखी जाए।

नागपंचमी/महेन्द्र तिवारी

## श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना का पर्व

भारत विविधताओं और त्योहारों की भूमि है, जहां हर पर्व किसी न किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक पक्ष से जुड़ा होता है। इन्हीं पर्वों में एक विशेष स्थान रखता है नागपंचमी, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति श्रद्धा अर्पण का अवसर होता है। हिन्दू धर्म में नागों को देवताओं का दर्जा प्राप्त है और वे कई धार्मिक कथाओं और पुराणों में विशेष रूप से वर्णित है।

नागों का संबंध सृष्टि के आरंभ से ही रहा है। शेषनाग को भगवान विष्णु का आसन माना जाता है, वहीं वासुकी नाग भगवान शिव के गले में शोभायमान हैं। महाभारत में नागराज तक्षक का उल्लेख आता है, जिन्होंने राजा परीक्षित को दंश दिया था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण आदि में नागों की उत्पत्ति, उनका महत्त्व और उनसे जुड़ी कथाएं स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भय, काल, सर्पदंश और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है ऐसा विश्वास है। इस दिन लोग नाग को दूध, चावल, हल्दी, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करते हैं। मिट्टी से नाग की आकृति बनाकर अथवा दीवारों पर नाग चित्रित कर पूजा की जाती है। विशेष रूप से महिलाएं इस दिन व्रत रखती है और अपने परिवार की रक्षा तथा समृद्धि की कामना करती हैं। नागपंचमी केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व प्रकृति के हर अंग का सम्मान करने की सीख देता है। नाग, जो कृषि आधारित समाज में प्राकृतिक पारिस्थितिकी का हिस्सा हैं, उनकी पूजा संरक्षण की भावना को भी जागृत करती है। नागपंचमी आज के दौर में हमें पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। सर्प पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे खेतों को चूहों जैसे कीटों से बचाते हैं, लेकिन अंधविश्वास के कारण बहुत बार नागों को मार दिया जाता है। नागपंचमी के माध्यम से यह संदेश दिया जाना चाहिए कि जीवों के साथ दया, और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। नागपंचमी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि गहराई से जुड़ी धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति प्रेम का प्रतीक है।

# ट्रंप की टैरिफ रणनीति

अर्थव्यवस्था

प्रो. लल्लन प्रसाद

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ रणनीति ने वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता का वातावरण पैदा कर दिया है। आयात-निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी के ऊपर अमेरिका के साथ समझौता करना अधिकांश देशों के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। ट्रंप के लिए अमेरिका पहले बाकी सब बाद में। अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए उन्होंने जो बातें कही थी उन पर तेजी से अमल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि व्यापार, टैक्स, इमीग्रेशन और विदेशी मामलों में जो नीतियां अपनाई जाएंगी उसमें अमेरिका के लोगों के हित को प्राथमिकता दी जाएगी। अपने देशवासियों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था कि अमेरिका में बनी चीजे खरीदें और अमेरिकंस को नौकरी दें, अमेरिका को फिर से पहले की तरह, शक्तिशाली, संपन्न और गौरवशाली राष्ट्र बनाएं। अमेरिका का व्यापार घाटा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने टैरिफ नीति में व्यापक परिवर्तन की घोषणा कर दी। अधिकांश देशों के साथ घाटे में व्यापार को रोकने के लिए आयात पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की जिसने अधिकांश राष्ट्रों को समझौते के टेबल पर बैठने को मजबूत कर दिया, इसमें छोटे और बड़े सभी राष्ट्र शामिल हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और छोटे राष्ट्रों ने उनकी बात आसानी से मान ली, किंतु विकसित और कई विकासशील देशों ने इसका का विरोध किया।

कुछ राष्ट्रों के साथ समझौता हो चुका है किंतु अभी बड़ी संख्या में ऐसे राष्ट्र हैं जो उनके द्वारा प्रस्तावित टैरिफ मानने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका में रह रहे प्रवासी नागरिक जो अपने आमदनी का कुछ हिस्सा अपने देश में अपने परिवार के लोगों को भेज रहे थे; उस पर पहली बार टैक्स लगाया गया। अमेरिकी इमीग्रेशन नीति में व्यापक परिवर्तन किया गया। अमेरिकी कंपनियों द्वारा विदेशियों की नियुक्ति पर अंकुश लगाए जा रहे हैं। कंपनियों से कहां जा रहा है कि वह दूसरे देशों में अपने प्लांट न लगाकर अमेरिका में ही उत्पादन करें। शुरू में उन्होंने जो टैरिफ रेट प्रस्तावित किए उनमें कंबोडिया, लॉओस, म्यांमार, बांग्लादेश, सर्बिया, थाईलैंड, वोस्निया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका को 30% से 40% एवं ट्यूनीशिया, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान और मलेशिया को 25% से 29% के ब्रैकेट में शामिल किया। न्यूनतम टैरिफ पहले 10% रखा था बाद में इसे बढ़ाकर 15% कर दिया। टेढ़ी उंगली से घी निकालने की नीति अपनाई, पहले जो तारीख तय किया उससे कुछ देश उनके आगे झुक गए, फिर उन्होंने 1 अगस्त की तारीख दी है जिसके बाद भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अप्रैल 2025 में

अमेरिकी प्रशासन ने वादा किया था 90 दिन में 90 देशों के साथ समझौता कर लेंगे, लेकिन अब तक मात्र पांच देशों के साथ अमेरिका का टैरिफ समझौता हो सका जिसमें ब्रिटेन, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस शामिल हैं।

यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ अभी तक समझौता नहीं हो पाया, ट्रंप के ही शब्दों में उन देशों के साथ समझौते के 50-50 परसेंट चांस है। ब्रिक्स देशों पर ट्रंप ने 10% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की क्योंकि उनके अनुसार ये देश अमेरिकी हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अमेरिकी डॉलर को ट्रंप दुनिया के मुद्राओं का बादशाह मानते हैं और इसको चुनौती देने वाले सभी देशों के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दे रहे रहे हैं। ब्राजील के ऊपर तो उन्होंने 50% टैरिफ लगाने तक की धमकी दे दी है जिसका वहां के राष्ट्रपति ने विरोध किया है। बदले में अमेरिकी वस्तुओं पर भी 50% टैरिफ लगाने की बात की। बाहर से आयात होने वाली वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा भारी टैरिफ लगाने या प्रतिबंधित करने से बहुत से राष्ट्रों को भारी नुकसान की आशंका है जो उनके मुख्य उत्पाद हैं और जिनका अमेरिका में बड़ी मात्रा में अब तक आयात होता रहा है, जैसे टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, जेम्स एवं ज्वेलरी, फार्मा प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट्स और व्हीकल्स आदि। जिन चीजों की अमेरिका में उनकी जरूरत से अधिक पैदावार है जैसे कृषि और डेयरी पदार्थ उनके लिए ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के और देश अपना बाजार अमेरिका के लिए पूरी तरह से खोल दें, भारत पर भी जिसके लिए दबाव डाल रहे हैं।

भारत के 33 अरब डॉलर के रत्न और आभूषण निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 30% है। अमेरिका के जेनेरिक दवा आयत के 47% हिस्से की आपूर्ति भारत करता है। अमेरिका से भारत मुख्य रूप से खिनज ईंधन, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर मशीनरी और विद्युत मशीनरी के अलावा चिकित्सा उपकरण, धातुएं सिक्के, वस्त्र और लोहे, इस्पात और अल्युमिनियम की वस्तुएं भी आयात करता है 2030 तक दोनों देशों के बीच में 500 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है, 2024 में दोनों देशों के बीच 129 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ हुआ था, अमेरिका का व्यापार घाटा भारत के साथ 48 बिलियन डॉलर था। ऊर्जा सुरक्षा दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अमेरिकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। 2023 में भारत में अमेरिकी निवेश का मूल्य लगभग 50 बिलियन डॉलर था। अमेरिका पर भारत का 216 बिलियन डॉलर का कर्ज है जो अमेरिकी ट्रेजरी बांड में भारत के निवेश के रूप में है। टैरिफ को लेकर दोनों देशों में वार्ता के कई दौर हो चुके हैं किंतु अभी तक समझौता नहीं हो पाया है।

अमेरिका ने जिन देशों को 1 अगस्त तक समझौता करने का अल्टीमेटम दिया है उसमें भारत नहीं है। अभी तक दोनों ओर से सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। कृषि और डेयरी पदार्थों के लिए विशेष रूप से अमेरिका भारत का बाजार अपने लिए टैरिफ मुक्त चाहता है जिसके लिए भारत तैयार नहीं है क्योंकि इन पर करोड़ों लोगों का जीवन-यापन निर्भर है। भारत को अमेरिका सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में गिनता है, भारत से निर्यात होने वाली कई वस्तुओं पर उसने टैरिफ कम करने की मांग रखी है। डिजिटल ट्रेड, सेवाओं, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और कयी औद्योगिक पदार्थों के भारत से निर्यात पर टैरिफ में कमी के संकेत भारत की ओर से दिए जा चुके हैं। पहली अगस्त तक पूरे समझौते की संभावना कम है किंतु अंतरिम समझौता हो सकता है।

*(लेख में विचार निर्यात हैं)*

भारत को अमेरिका सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में गिनता है, भारत से निर्यात होने वाली कई वस्तुओं पर उसने टैरिफ कम करने की मांग रखी है। डिजिटल ट्रेड, सेवाओं, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और कयी औद्योगिक पदार्थों के भारत से निर्यात पर टैरिफ में कमी के संकेत भारत की ओर से दिए जा चुके हैं। पहली अगस्त तक पूरे समझौते की संभावना कम है किंतु अंतरिम समझौता हो सकता है

## फलों के राजा 'आम' का आज भी दिलों पर राज कायम

- आम, कम से कम भारतीयों के लिए, फल से कहीं बढ़ कर है, अहसास है, पारंपरिक स्वाद है, संस्कृति है। फिर भी, दुनिया भर में '1,400 से ज्यादा किस्मों' के साथ, इसकी असली ताकत इसकी बेजोड़ विविधिता और इस्तेमाल में निहित है
- आम हर मौसम में खुद को नया रूप देता है, और साथ ही फलों के निर्विवाद राजा के रूप में अपना स्थान बनाए रखता है। इसका दोहरा स्वभाव- पकने पर मीठा और रसीला, कच्चा होने पर खट्टा-प्रयोग करने का अवसर देता है

वरिष्ठ पत्रकार स्व. निखिल चक्रवर्ती के योग्य बेटे सुमित चक्रवर्ती के लंबी बीमारी के बाद निधन निडर ईमानदार पत्रकारिता के युग का अंत पास आ गया है, जब पत्रकार सब कुछ लुटा कर लोकतंत्र को जिलाये रखते थे। पालतू शेर- हाथियों और रंगपुते मसखरों का समूह नहीं बने थे। श्रद्धांजलि

मृणाल पांडे, पत्रकार
@MrinalPande1

मंदिरों में भगदड़ जयसिंह रावत

# कब रुकेंगी त्रासदियां

हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में 27 जुलाई रविवार को जो कुछ हुआ, वह किसी अप्रत्याशित घटना की तरह नहीं था। यह हादसा एक बार फिर से उस सच्चाई को सामने लाता है कि धार्मिक आस्था का उफान जब प्रशासनिक विवेक, स्थान की क्षमता और वैज्ञानिक भीड़ प्रबंधन पर भारी पड़ता है, तो आस्था का यह सैलाब त्रासदी में बदल सकता है। उस दिन मंदिर के मुख्य मार्ग की सीढ़ियों पर अचानक भगदड़ मच गई। कहा गया कि किसी ने यह अफवाह फैला दी कि रेलिंग में करंट दौड़ रहा है। नतीजा यह हुआ कि 8 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई और लगभग 30 श्रद्धालु घायल हो गए। यह घटना हमें बताती है कि हम आज भी उन्हीं भूलों को दोहरा रहे हैं जिनका इतिहास दशकों पुराना है।

मनसा देवी मंदिर पहाड़ी पर स्थित एक अत्यधिक लोकप्रिय शक्तिपीठ है, जहां सावन और नवरात्र जैसे पर्वों पर श्रद्धालुओं की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह अक्सर उतनी ही कमजोर साबित होती है जितनी कि श्रद्धा प्रबल। यह पहली बार नहीं है जब हरिद्वार में ऐसा हुआ हो। इससे पहले 1986 के कुंभ मेले की भगदड़ में लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2011 में हर की पैड़ी पर भी एक भगदड़ में 20 लोग मारे गए थे। इसी प्रकार 8 नवम्बर 2011 को ही शांतिकुंज के एक कार्यक्रम में भी भगदड़ में 20 श्रद्धालुओं की मौत और 30 घायल हो गए थे। इन हादसों का पैटर्न लगभग एक जैसा रहा है, अत्यधिक भीड़, संकरे रास्ते, अफवाहें और प्रशासनिक लापरवाही। भगदड़ हादसों के मामले में हरिद्वार अकेला नहीं है। देश के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी इसी तरह की घटनाएं बार-बार होती रही हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक स्वयंभू बाबा के सत्संग में भगदड़ मची, जिसमें 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2022 में वैष्णो देवी मंदिर में भी नववर्ष के मौके पर भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की जान गई। 2008 में हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में चट्टान खिसकने की अफवाह से भगदड़ मची थी जिसमें 162 लोग मारे गए थे। 2023 में रामनवमी के अवसर पर वहीं एक और भगदड़ हुई, जिसमें 36 श्रद्धालु मरे। इसी महीने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान टेंट गिरने और दीवार ढहने से दो लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े महज

संख्याएं नहीं, बल्कि व्यवस्थागत असफलताओं के प्रमाण हैं। प्रश्न यह है कि आखिर ये घटनाएं बार-बार क्यों घट रही हैं? एक कारण तो यह जरूर है कि भीड़ को आयोजन और आयोजन स्थल की सफलता का मापदंड माना जाता है। सरकारें और धार्मिक संस्थाएं जितनी अधिक भीड़ जुटा पाती हैं, उसे उतनी ही बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित करती हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को लाखों और करोड़ों में गिनाया जाता है, और यह मान लिया जाता है कि आस्था जितनी व्यापक होगी, उतनी ही मान्यता और चढ़ावा भी मिलेगा, परंतु इस मानसिकता में यह भूल जाती है कि किसी भी स्थल की एक सीमा होती है, जिसे कैरीइंग कैपेसिटी कहा जाता है। कैरीइंग कैपेसिटी का अर्थ है किसी स्थल की वह अधिकतम सीमा जहां तक वह पर्यावरणीय, भौगोलिक और संरचनात्मक रूप से भीड़ को सुरक्षित रूप से संभाल सकती है। मनसा देवी मंदिर जैसे स्थलों पर यह सीमा सीमित होती है, सीढ़ियां संकरी हैं, रेलिंग पुरानी हैं, और ऊपर-नीचे आने-जाने का मार्ग एक ही है। ऐसी स्थिति में यदि हजारों की संख्या में लोग एक साथ एक ही दिशा में बढ़ते हैं और अचानक अफवाह या घबराहट फैलती है, तो भगदड़ अवश्यंभावी हो जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में अधिकांश धार्मिक स्थलों पर ऐसी स्पष्ट कैरीइंग कैपेसिटी निर्धारित नहीं की जाती और न ही भीड़ को उसी अनुसार रोका जाता है। जब तक यह वैज्ञानिक आधार पर तय नहीं किया जाएगा कि किस पर्व पर किस स्थल पर कितने लोग एक समय में प्रवेश कर सकते हैं, तब तक सुरक्षा सिर्फ भाग्य पर आधारित होगी।

प्रशासन कई बार दावा करता है कि उसने पर्याप्त इंतजाम किए थे, सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, पुलिस बल तैनात किया गया था, रूट प्लान तैयार था, परंतु जब हादसा हो जाता है, तो यही व्यवस्थाएं कागजों में ही सीमित पायी जाती हैं। मनसा देवी मंदिर की घटना में भी यही हुआ। एक अफवाह ने समूची व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। दूसरी ओर, धार्मिक संस्थाओं की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कई बार आयोजक भीड़ को लेकर कोई वैज्ञानिक अनुमान नहीं लगाते, न ही किसी प्रकार की पूर्व अनुमति की प्रक्रिया का पालन करते हैं। हाथरस की घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है। न आयोजन का कोई नियंत्रण था, न किसी एजेंसी से सहमति ली गई थी, और न ही आपातकालीन प्रबंधन की कोई योजना थी। धार्मिक आस्था को आंकड़ों, भीड़ या प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि विवेक और जिम्मेदारी के साथ जोड़ना होगा। जब तक भीड़ को आयोजन की सफलता और चढ़ावे का पैमाना माना जाता रहेगा, तब तक मनसा देवी, नैना देवी, हाथरस या वैष्णो देवी जैसी त्रासदियां दोहराई जाती रहेंगी।

निर्बल के बल राम ओशो

लाओत्से गुजर रहा है एक बाजार से। मेला भरा है। एक बैलगाड़ी उलट गई है; दुर्घटना हो गई है। मालिक था, हड्डी-पसलियां टूट गई हैं। बैल तक बुरी तरह आहत हुए हैं। गाड़ी तक चकनाचूर हो गई है। एक छोटा बच्चा भी गाड़ी में था; दुर्घटना जैसे उसे छुई ही नहीं। तुमने अक्सर देखा होगा, कभी किसी मकान में आग लग गई है, सब जल गया, और एक छोटा बच्चा बच गया। कभी कोई छोटा बच्चा दस मंजिल ऊपर से गिर जाता है, और खिलखिला कर खड़ा हो जाता है, और चोट नहीं लगती। लोगों में कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके न कोए। इसमें परमात्मा का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि परमात्मा को क्या भेद है--कौन छोटा, कौन बड़ा! नहीं, राज कुछ और है। वह लाओत्से जानता है। बच्चा कमजोर है। अभी बच्चा सख्त नहीं हुआ। अभी उसकी हड्डियां पथरीली नहीं हुईं। अभी उसकी जीवन-धार तरल है। जितनी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी उतनी ही ज्यादा चोट लगेगी। बैलगाड़ी उलटेगी, तो बूढ़े को ज्यादा चोट लगेगी, बच्चे को न के बराबर। क्योंकि बच्चा इतना कोमल है; जब गिरता है जमीन पर तो उसका कोई प्रतिरोध नहीं होता जमीन से। वह जमीन के खिलाफ अपने को बचाता नहीं। उसके भीतर बचाव का कोई सवाल ही नहीं होता; वह जमीन के साथ हो जाता है। वह गिरने में साथ हो जाता है। वह समर्पण कर देता है, संघर्ष नहीं। कठोरता में संघर्ष है। जब तुम गिरते हो तो तुम लड़ते हुए गिरते हो, तुम गिरने के विपरीत जाते हुए गिरते हो, तुम अपने को बचाते हुए गिरते हो, तुम मजबूरी में गिरते हो। तुम्हारी चेष्टा पूरी होती है कि न गिरें, बच जाएं, आखिरी दम तक बच जाएं। तो तुम्हारी हड्डी-हड्डी, रोएं-रोएं में सख्ती होती है कि किसी तरह बच जाएं। और जब बचने का भाव होता है तो सब चीजें सख्त हो जाती हैं। बच्चे को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। वह ऐसे गिरता है जैसे कोई नदी की धार में धार के साथ बहता हो। तुम धार के विपरीत तैरते हुए गिरते हो। तुम्हारी विपरीतता में, तुम्हारी सख्ती में ही तुम्हारी चोट छिपी है। बच्चा बच जाता है। लाओत्से खड़ा है नदी के किनारे। एक आदमी डूब गया है। लोग उसकी लाश को खोज रहे हैं। आखिर में लाश खुद ही पानी के ऊपर तैर आई है। और लाओत्से बड़ा चकित होता है: जिंदा आदमी तो डूब गया और मुर्दा ऊपर तैर आया, मामला क्या है? क्या नदी जिंदा को मारना चाहती थी और मुर्दे को बचाना चाहती है?

## रीडर्स मेल

### संदेह का लाभ न मिले

21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने, 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सात विस्फोटों के आरोपियों को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया है। इसका क्या मतलब माना जाए? या तो पैरवी करने वालों ने पैरवी ढंग से की नहीं या न्यायपालिका का भ्रष्टाचार जैसा कोई विषय रहा। न्याय व्यवस्था में लगे इस देश के पढ़े-लिखे लोग चाहे वे पुलिस के हों या न्यायपालिका के, क्या यह समझने में असमर्थ है कि समाज का धीरे-धीरे विश्वास कम क्यों होता जा रहा है? यदि संदेह का लाभ आतंकवादियों को इस प्रकार दिया जाता रहा तो क्या इससे समाज अराजकता की ओर नहीं धकेला जा रहा? आखिर संदेह का लाभ उन लोगों को क्यों नहीं मिलता जो पीड़ित हैं? ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब न्यायपालिका अपराधी को संदेह का लाभ देती है और छूटने पर वह फिर उससे बड़ा अपराध करता है। इसलिए न्यायपालिका को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसे आतंकी हमलों में 'संदेह का लाभ' किसे मिलना चाहिए?

युवराज पल्लव, मेरठ

### प्रकृति का संतुलन जरूरी

प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी जीवों की अहमियत है, इसीलिए हमारी संस्कृति में युगों-युगों से नाग पंचमी के अवसर पर नाग पूजा की परंपरा चली आ रही है। नाग किसानों का सबसे बड़ा मित्र है। चूहा फसल को बर्बाद करते हैं, तो नाग चूहा को अपना शिकार बना लेते हैं। आज बढ़ती आबादी, शहरीकरण और संस्कृति के पराभव की वजह से नाग और इंसान एक दूसरे के शत्रु बन बैठे हैं। नागों के प्राकृतिक आवास में कमी होने की वजह से वे इंसानों के बीच आ जाते हैं, और इंसान और नाग का संघर्ष शुरू हो जाता है। कम प्रजाति के नाग विषैले होते हैं।

हिमांशु शेखर, गयाजी

### बिहार में लगातार हो रहा अपराध

बिहार में एक शर्मनाक घटनाक्रम सामने आया है। यहां एक महिला होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दौरान बेहोश हो गई। उसे इलाज के लिए ले जाने के समय एंबुलेंसकर्मियों-तकनीशियन और ड्राइवर-ने रेप की घटना को अंजाम दिया। निःसंदेह इस घटना से बिहार को कलंकित होना पड़ा है। इस पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान द्वारा बिहार में बेकाबू हिंसा का हवाला देते हुए भाजपा-जद (यू) सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बिहार की राजनीति में यह ऐसा एक दौर है जहां लगातार हिंसात्मक घटनाएं हो रही है। इसमें सरकार की निष्क्रियता और विफलता भी साफ परिलक्षित होती है। विपक्ष ने बिहार की सरकार को राक्षस राज की संज्ञा दी है और मुख्यमंत्री को अचेत अवस्था में बताया है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार सरकार पर पहले से ही हमलावर है और चिराग पासवान के कारण राजद को एक बड़ा अवसर मिला है। मेरा मानना है कि यदि बिहार में हिंसा का दौरा नहीं थमता है तो यह परेशानी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को भारी पड़ने वाला है। बिहार में इस समय हिंसा की घटनाएं बेकाबू है जिसको रोकना में सरकार नाकाम रही है और यदि यह हाल रहा तो आने वाले चुनाव में बीजेपी और भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। हास्यास्पद बात यह है कि लालू जी के शासन को विपक्ष जंगलराज बताता है।

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं
राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया बिहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428